

स्वदेशी पत्रिका

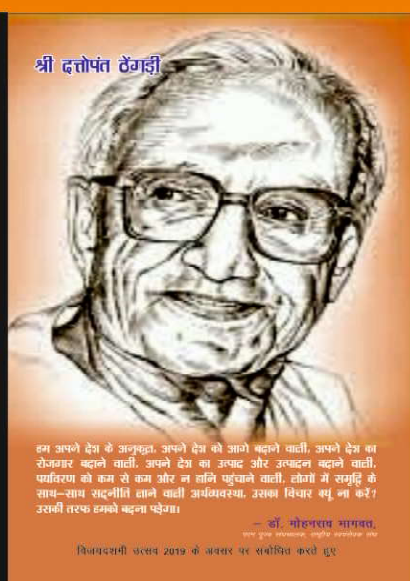
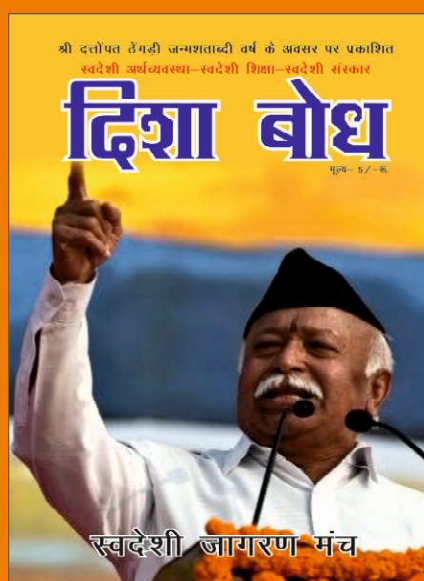
मूल्य 15/-रु.

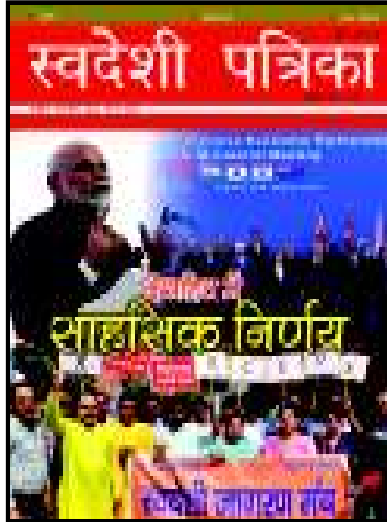
कार्तिक-मार्गशीर्ष 2076, नवंबर 2019



देशहित में साहसिक निर्णय

राष्ट्ररूषि दत्तोपंत ठेंगडी जन्मशताब्दी वर्ष





वर्ष-27, अंक-11
कार्तिक-मार्गशीर्ष 2076 नवंबर 2019

संपादक
अजेय भारती

सह-संपादक
अनिल तिवारी

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन
सुदामा दीक्षित

कार्यालय
धर्मक्षेत्र, सेक्टर-8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली-110022
से प्रकाशित

दूरभाष : 011-26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर
दास महाजन द्वारा कॉम्प्यूटेंट बाइन्डर्स
(प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली-32
से मुद्रित।

पाठकनामा/उन्होंने कहा **4**
समाचार परिक्रमा **34-38**



तृतीय मुख्य पृष्ठ
चतुर्थ मुख्य पृष्ठ

39
40

आवरण कथा - पृष्ठ-6

देशहित में साहसिक निर्णय

डॉ. अश्वनी महाजन



- 1 मुख्य पृष्ठ
- 2 द्वितीय मुख्य पृष्ठ

08 आवरण कथा-2

धीरे से लगा चीन को जोर का झटका

..... स्वदेशी संवाद

11 जन्मशताब्दी पर विशेष

राष्ट्रत्रय दत्तोपंत टेंगडी (1920-2004)

..... सरोज कुमार मित्र

13 आजकल

उपयोगी और विनाशकारी मशीनों के बीच का फर्क

..... अनिल तिवारी

16 विचार

छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहन जरूरी

..... डॉ. भरत झुनझुनवाला

18 विश्लेषण

ऑनलाईन खरीददारी से छोटे दुकानदारों को खतरा

..... सूर्यप्रकाश अग्रवाल

21 कृषि

कृषि सब्सिडी से विकास: मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं

..... देविन्दर शर्मा

23 जल प्रबंधन

कहां गुम हो गये हैं पोखर-तालाब

..... डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र

26 मुद्दा

प्लास्टिक कचरे से खतरा

..... के.के. श्रीवास्तव

29 दोदूक

क्यों नहीं हो पाया भारत अमरीकी व्यापार समझौता?

..... स्वदेशी संवाद

31 स्वदेशी अर्थव्यवस्था-स्वदेशी शिक्षा-स्वदेशी संस्कार

दिशा बोध

..... दीपक शर्मा



पाठकनामा

एमआरपी के साथ एमएसपी भी जरूरी

हमारे देश में कोई निर्माता या उत्पादक नहीं बनना चाहता बल्कि हर कोई दलाल या ट्रेडर बनना चाहता है क्योंकि ट्रेडर का मुनाफा उत्पादक से बहुत अधिक है तथा जौखिम बहुत कम। हमें इस वातावरण को बदलना होगा।

देश में स्वदेशी निर्माण के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है वस्तुओं पर एमआरपी छापना। उपभोक्ता को ये पता ही नहीं होता कि ये माल उत्पादक ने कितने में बेचा। इस जानकारी के अभाव में उपभोक्ता व उत्पादक को नुकसान होता है तथा दलाल को असीमित मुनाफा होता है। यही कारण है हमारे देश में सब दुकानदार बने हैं दूसरों का माल बेच रहे हैं पर कोई उत्पादक नहीं बनना चाहता।

असल में एमआरपी के निर्धारण की कोई निश्चित प्रक्रिया व नियम ही नहीं है। उत्पादक अपने माल पर अधिक एमआरपी इसलिए छापता है ताकि दलाल को मनमर्जी मुनाफा हो और वो उसका माल बेचे।

अधिक एमआरपी उपभोक्ता को सामान उच्च लागत पर खरीदने के लिए मानसिक रूप से तैयार करते हैं। इसके बाद ट्रेडर उस सामान को 20 से 80% तक की कम कीमत पर बेचने का विज्ञापन करते हैं। फिर उपभोक्ता उस सामान को इस धारणा के साथ खरीदते हैं कि वह सस्ती कीमत पर मिल रहा है जबकि यह सच नहीं है। यह दिमागी खेल है।

इसके अलावा, जीएसटी के बाद एकसमान कर दर होने पर एमआरपी महत्वपूर्ण नहीं रहा है इसलिए उपभोक्ता को मजबूत बनाने के लिए उसे उत्पादक का बिक्री मूल्य पता होना चाहिए या फिर सरकार को एमआरपी तय करने का नियम बनाना चाहिए, जो निर्माता के बिक्री मूल्य पर आधारित हो जैसे उत्पादक के बिक्री मूल्य यानी पीएसपी का 25-30 प्रतिशत। साथ ही एमआरपी तथा पीएसपी दोनों मूल्य छापना अनिवार्य किया जाए।

वस्तु पर उत्पादक का बिक्री मूल्य छापने से सरकार का कर संग्रह भी बढ़ेगा। ये निर्णय उत्पादक तथा उपभोक्ता दोनों को सशक्त करेगा और देश में निर्माण बढ़ेगा व देश मजबूत होगा।

राकेश्वर वर्मा, (ई-मेल द्वारा)

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

“धर्मक्षेत्र” शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर-8, रामकृष्णपुरम्,
नयी दिल्ली-110022

दूरभाष : 011-26184595 • ई-मेल:

swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क 'स्वदेशी पत्रिका' दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए

आजीवन सदस्यता शुल्क: 15,00 रुपए

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740

IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

यदि शुल्क जमा करने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

कहा-अनकहा



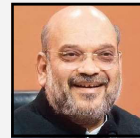
भारत के 'लौह पुरुष' ने देश की एकता एवं अखण्डता सुनिश्चित की। उनका साहसिक नेतृत्व आज भी पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी देश सेवा के लिए सभी भारतवासी सरदार पटेल के प्रति सदैव कृतज्ञ रहेंगे।

रामनाथ कोविन्द (राष्ट्रपति, भारत)



जब भी मैं आरसीईपी में भारत को शामिल करने के आलोक में भारतीय हितों का आकलन करता हूं, तो मुझे सकारात्मक उत्तर नहीं मिलता; न ही गांधी जी की आत्मनिर्भरता की नीति और न ही मेरा विवेक मुझे आरसीईपी में शामिल होने के लिए अनुमति देता है।

नरेंद्र मोदी (प्रधानमंत्री, भारत)



मुझे पूर्ण विश्वास है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया यह ऐतिहासिक निर्णय (राम मंदिर) अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगा। यह निर्णय भारत की एकता, अखंडता और महान संस्कृति को और बल प्रदान करेगा।

अमित शाह (गृहमंत्री, भारत)



आरसीईपी समझौते को 'ना' के बाद डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के लिए भारत के पास विदेशी भुगतान, ई-कॉमर्स और सोशल मीडिया कंपनियों को अपना डाटा भारत में ही रखने के लिए मजबूर करने का अवसर है।

डॉ. अश्वनी महाजन (सहसंयोजक, स्वदेशी जागरण मंच)

राष्ट्ररूषि दत्तोपंत ठेंगड़ी की जन्मशताब्दी

राष्ट्ररूषि दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने कई संगठनों का निर्माण किया, लेकिन भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ और स्वदेशी जागरण मंच की अधिक चर्चा की जाती है। भारतीय मजदूर संघ जहां आज दुनिया का सबसे बड़ा मजदूर संगठन बनकर उभरा है, वहीं किसान संघ की भी कृषि क्षेत्र में एक बड़ी भूमिका है। स्वदेशी जागरण मंच, देश के समक्ष आर्थिक चुनौतियों के मद्देनजर एक बड़ा आंदोलनात्मक मंच बन कर उभरा है और भूमंडलीकरण और उसके प्रभावों से उत्पन्न मुद्दों पर पैनी नजर रखते हुए सरकारों पर लगातार दबाव बनाने का काम कर रहा है।

एक ऐसे समय में जब मजदूर संगठनों पर साम्यवादी दलों व कांग्रेस का वर्चस्व था, भारतीय मजदूर संघ की स्थापना कर, मजदूर क्षेत्र के चिंतन को प्रभावित करने का काम ठेंगड़ी जी ने किया। साम्यवादी संगठनों के वर्ग संघर्ष को बढ़ावा देकर अराजकता की स्थिति पैदा करने की रणनीति के सामने मजदूर क्षेत्र में अधिकारों के प्रति आग्रह के साथ ही साथ राष्ट्रवादी चिंतन को बढ़ावा देने का काम भारतीय मजदूर संघ ने किया। मजदूरों और प्रबंधन के बीच अनावश्यक कड़वाहट, न होकर आग्रह राष्ट्रहित में काम करते हुए उत्पादन को अधिकतम करने का अभ्यास, भारतीय मजदूर संघ का ध्येय वाक्य बन गया। 'राष्ट्र के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम'। मजदूरों में कर्तव्य भाव और राष्ट्र भाव जागरण, समभाव, देश प्रेम की शिक्षा, भारतीय मजदूर संघ की विशेषता है।

मजदूर संघ की स्थापना और विस्तार के साथ साम्यवादी चिंतन को जन समर्थन कम होता गया और अंततोगत्वा हम देखते हैं कि साम्यवाद देश में आखिरी सांसें गिन रहा है और राष्ट्रवादी चिंतन का व्यापक विस्तार हुआ है। वर्ग संघर्ष और अराजकता की बजाय राष्ट्रवाद और देश प्रेम का जोर दिखाई देने लगा है। साम्यवादी संगठन किस प्रकार से देश विरोधी और सांप्रदायिक गतिविधियों में संलग्न होकर देश में एक और विभाजन (टुकड़े) करने की कोशिश करते हैं, वह पूरी तरह से उजागर हो गया है।

देश में किसान क्षेत्र में भी संगठन का अभाव था। किसानों की स्थिति में एकरूपता नहीं है। कुछ क्षेत्र सिंचित हैं, शेष सिंचित नहीं है। कुछ किसान बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। अलग-अलग प्रकार की फसलें, मिट्टी और अन्य भौगोलिक स्थितियां हैं। भारतीय किसान संघ की स्थापना के बाद उनकी समस्याओं के निराकरण और उनमें राष्ट्र भाव जागरण हेतु प्रयास किए गए। किसान संघ को नारा दिया— 'देश के हम भंडार भरेंगे, लेकिन कीमत पूरी लेंगे'। आज भारतीय किसान संघ किसानों और राष्ट्र के हितों को सजग प्रहरी है।

1990 के दशक में जब भूमंडलीकरण और नई आर्थिक नीति के नाम पर विदेशी आर्थिक आक्रमण तीव्र हुआ तो इसके खिलाफ देश में जन आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। इसमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त समाजवादी और साम्यवादी संगठन और राजनीतिक दल भी शामिल थे। लेकिन नेतृत्व की कमी के कारण यह आंदोलन समन्वित प्रकार से आगे नहीं बढ़ रहा था। ऐसे में दत्तोपंत जी की सूझबूझ से स्वदेशी जागरण मंच के रूप में एक ऐसी रचना का सूत्रपात हुआ, जो समस्त ऐसी शक्तियों जो देश की आर्थिक आजादी को अक्षुण्ण रखने में सहयोगी हो सकती है, को साथ लेकर चल सके। स्वदेशी जागरण मंच की रचना एक संगठन के रूप में नहीं बल्कि एक मंच के रूप में हुई। एक ऐसा मंच जिसमें स्वदेशी के आदर्शों से सहमति रखने वाले लोग, मुद्दों के आधार पर एक साथ एक मंच पर आ सकें और विचारधाराओं की सीमाओं को तोड़ते हुए, राष्ट्रीय महत्व के आर्थिक मुद्दों पर एक साथ लड़ने के लिए भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, विद्या भारती, लघु उद्योग भारती, सहकार भारती, ग्राहक पंचायत, जनवासी कल्याण आश्रम, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सभी को इस मंच की निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया गया। हर विचारधारा के लोग मंच के साथ जुड़कर काम करने लगे। मंच का स्वरूप और स्वभाव आज भी वैसा ही बना हुआ है। मजदूर संघ, किसान संघ और स्वदेशी जागरण मंच के अलावा ठेंगड़ी जी ने 1983 में सामाजिक समर सत्ता मंच और 1991 में सर्वपथ समादर मंच की भी स्थापना की।

ठेंगड़ी जी ने 125 से भी अधिक पुस्तकों की रचना की। राष्ट्र की अवधारण को लेकर प.पूजनीय गुरु गोवलरकर जी के भाषणों पर आधारित पुस्तक 'राष्ट्र', पूर्व में साम्यवादी चिंतक रहे प्रो. एम.जी. बोकरे की 'हिन्दु इक्नॉमिक्स', श्री दयाशंकर जी की 'दि प्लेड पॉवर्टी' सहित अनेकों पुस्तकों की प्रस्तावनाएं लिखी, जो उनके सामाजिक, राष्ट्रीय एवं आर्थिक चिंतन की व्यापकता और गहनता को परिलक्षित करती हैं। जहां वे साम्यवाद के प्रबल विरोधी थे, अमेरिका और पश्चिम के देशों के पूंजीवाद के भी वे उतने ही बड़े विरोधी थे। उनका मानना था कि सर्वसमावेशी विकास के लिए एक नए मार्ग की आवश्यकता है, जिसे हम 'तीसरा मार्ग' यानि 'थर्ड वे' कह सकते हैं।

पश्चिमी विचारकों की 'राष्ट्र' की अवधारणा और उसमें शामिल विरोधाभासों को उदघाटित करते हुए उन्होंने भारत की 'राष्ट्र' की अवधारणा को स्पष्ट करने का काम किया। गुरुजी के उद्योधनों को संकलित करते हुए राष्ट्र पुस्तक में लिखित अपनी प्रस्तावना में इस विषय को प्रतिस्थापित किया और यह साबित किया कि भाषा, प्रांत और वर्गों की विविधताओं के बीच सांस्कृतिक एवं सामाजिक एकता को प्रदर्शित करता हुआ, भारत एक 'राष्ट्र' है।

जीवन पर्यन्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के नाते निरंतर समाज जीवन में संगठनों का निर्माण एवं विस्तार, अपनी लेखनी द्वारा असत्य अवधारणाओं का सफलतापूर्वक खंडन, आर्थिक साम्राज्यवाद चाहे वह साम्यवादी साम्राज्यवाद हो अथवा पूंजीवाद साम्राज्यवाद उनके विरुद्ध आंदोलनों का निर्माण, साम्यवादियों के चुंगूल से मजदूर आंदोलन को मुक्त करवाना, ये सभी अद्भूत और असंभव से दिखने वाले कार्यों के लिए समाज ने उन्हें एक 'महामानव' और राष्ट्ररूषि जैसे संबोधन दिए, जो उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व का वर्णन करते हैं।

देशहित में साहसिक निर्णय

पिछले कुछ समय से भारत द्वारा क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) के नाम पर 10 आसियान देशों जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और चीन के साथ-साथ एक नए मुक्त व्यापार समझौते की कवायद चल रही थी, जिस पर 4 नवंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बैंकॉक में आरसीईपी शिखर सम्मेलन में इस घोषणा के साथ कि भारत आरसीईपी में शामिल नहीं होगा, विराम लग गया है। यह समझौता केवल नाम से ही व्यापक नहीं था, बल्कि वास्तव में यह भी अत्यंत विस्तृत समझौता प्रस्तावित था, जिसमें निवेश, कृषि, डेयरी, मैन्यूफैक्चरिंग, ई-कॉमर्स, डाटा समेत तमाम विषय शामिल थे। इस समझौते का किसान, डेयरी में संलग्न लोग स्टील, केमिकल्स, टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल, साइकिल, टैक्सटाइल समेत विभिन्न क्षेत्र विरोध कर रहे थे। इस प्रस्तावित समझौते के व्यापक विरोध के चलते सरकार काफी ऊहापोह में थी कि यह समझौता किया जाए या नहीं। बीते दिनों में इस समझौते को भारत के अनुकूल बनाने के संदर्भ में कुछ विषय आरसीईपी में चले लेकिन ऐसा लगता है कि भारत के उन मुद्दों और चिंताओं का निराकरण नहीं हो पाया। अंततोगत्वा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस समझौते से बाहर आने की घोषणा से तमाम वो क्षेत्र जो इसका पुरजोर विरोध कर रहे थे, भारी राहत महसूस कर रहे हैं।

80 से 95 वस्तुओं पर आयात शुल्क शून्य हो जाते

इस समझौते का मूल विषय था वस्तुओं के आयातों पर शुल्क शून्य करना। मुक्त व्यापार समझौतों का मतलब होता है कि आयात शुल्कों को समाप्त कर वस्तुओं की आवाजाही को मुक्त बनाना। गौरतलब है कि इस प्रस्तावित समझौते में चीन से आने वाली 80 प्रतिशत वस्तुओं पर और अन्य देशों से आने वाली 90 से 95 प्रतिशत वस्तुओं पर आयात शुल्क को शून्य करने का प्रस्ताव था। हम जानते हैं कि इस समझौते में 10 आसियान देश भी शामिल थे। आसियान देशों के साथ हमारा मुक्त व्यापार समझौता पहले से ही है, जो 2011 में हुआ था। इस समझौते के बाद आसियान देशों से हमारा व्यापार घाटा लगभग तीन



आरसीईपी समझौता
प्रधानमंत्री के मेक इन
इंडिया, किसानों की
आय दोगुनी करना,
डिजिटल इंडिया, भारत
को मैन्यूफैक्चरिंग हब
बनाना आदि अनेकों
सपनों को धूमिल कर
देता। अब हम इन
मुद्दों पर और
जोर-शोर से आगे बढ़
सकते हैं।
— डॉ. अश्वनी महाजन



गुना बढ़ चुका है। इस समझौते में ना तो कोई निकलने का प्रावधान था और न ही पुनर्विचार का। इसके कारण देश के किसानों और उद्योगों को भारी नुकसान सहना पड़ा। लगभग एक माह पहले भारत के वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल ने इस समझौते पर पुनर्विचार के लिए आसियान मुल्कों को राजी कर लिया था, जो भारत के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। उधर जापान और साउथ कोरिया के साथ भी इसी प्रकार का मुक्त व्यापार समझौता यूपीए के शासनकाल में ही हो गया था। इसके कारण भी जापान और साउथ कोरिया के साथ हमारा व्यापार घाटा ढाई से तीन गुना बढ़ गया। कुल मिलाकर आरसीईपी देशों के साथ हमारा व्यापार घाटा 105 अरब डालर के लगभग है। यदि यह समझौता हो जाता तो शून्य आयात शुल्कों के कारण इन मुल्कों से आयातों की बाढ़ और ज्यादा भयानक रूप से बढ़ जाती। यही कारण है कि आरसीईपी में भारत के शामिल ने होने से भारत के उद्योग, डेयरी और कृषि क्षेत्र खुशी महसूस कर रहे हैं।

क्या थी डेयरी और कृषि की खास समस्या

यह जानना होगा कि हमारे छोटे-छोटे किसानों का मुकाबला किन विशालकाय कृषि उत्पादकों से होने वाला था। हमारे यहां 10 करोड़ किसान एवं गैर किसानों की जीविका डेयरी पर चलती है, जबकि न्यूजीलैंड का सारा डेयरी उत्पाद (जिस वे दुनिया भर में निर्यात करते हैं) मात्र 11.5 हजार डेयरियों से आता है और वे दुनिया के कुल डेयरी निर्यातों का 30 प्रतिशत हिस्सा रखते हैं। जापान अपने देश में चावल, गेहूं, कपास, चीनी और डेयरी के उत्पादकों के संरक्षण के लिए 33.8 अरब डालर (14,136 डालर प्रति किसान) की सहायता देता है, ताकि उसके किसानों का संरक्षण हो सके,

जबकि भारत में यह सहायता नगण्य है। इसलिए यदि हम यह सोचें कि हमारे किसानों को अन्य देशों में व्यापार पहुंच मिल जाती, तो यह गलत होता। लेकिन सस्ते कृषि उत्पादों के भारत में आयात से भारतीय किसान प्रतिस्पर्द्धा से जरूर बाहर हो जाते। डेयरी की बात करें तो न्यूजीलैंड के दूध पाउडर की कीमत मात्र 180 रु. प्रति किलो है जबकि भारत में दूध पाउडर की कीमत 290 प्रति किलो है। ऐसे में न्यूजीलैंड से शून्य आयात शुल्क पर डेयरी उत्पाद आने से भारत के डेयरी की रीढ़ ही टूट जाती।

निवेश समझौते की समस्या

2014 में नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद यह समस्या आई कि यूपीए सरकार द्वारा जो निवेश समझौते किये गये थे, उनके कारण निवेशकों ने भारत सरकार पर मुकदमें करने शुरू कर दिये कि उन मुल्कों के साथ समझौतों के अनुरूप सुविधाएं नहीं दी गईं और इसलिए उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। कई मुकदमों में विदेशी कंपनियां भारी मुआवजा लेने में सफल भी हो गईं। ऐसे में इन समझौतों से निजात पाने के लिए उन्हें रद्द करने की कार्यवाही की गई। लेकिन विडंबना यह थी कि इस आरसीईपी समझौते के बाद देश पुनः उसी जाल में फंस जाता। यही नहीं इस समझौते के बाद विदेशी कंपनियों द्वारा रायल्टी और टेक्नीकल फीस पर अंकुश भी समाप्त हो जाता। आरसीईपी समझौते से बाहर आने के बाद इस समस्या से भी निजात मिल पायेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरसीईपी से बाहर आने का यह निर्णय आसान नहीं था लेकिन यह भी उतना ही सच है कि उनके इस निर्णय से लघु उद्योग, किसान, डेयरी और मैन्यूफैक्चरिंग से जुड़े लोगों में खुशी की लहर है। हालांकि कुछ लोग यह कह रहे हैं कि जिस प्रकार से प्र

धानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया में अन्य मुल्कों के साथ नये रिश्ते बनाने के नाते जाने जाते हैं, आरसीईपी से बाहर आने का निर्णय उससे अलग दिखता है। लेकिन प्रधानमंत्री ने दुनिया को एक संदेश भी दिया है कि दुनिया से रिश्ते बनाने में हमें अपने देश और अपने लोगों के हितों को ही सर्वोपरि रखना चाहिए। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि आज भारत एक नया भारत है, और वह अपने देश की आकांक्षाओं के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। उनका यह निर्णय देश के हित में माना जा रहा है और इसके—दुक्के विरोध के अलावा शेष पूरा देश प्रधानमंत्री के इस निर्णय की सराहना कर रहा है।

जहां एक तरफ आसियान मुल्कों के साथ हुए पुराने समझौते पर पुनर्विचार शुरू हो गया है, वहीं जापान और साउथ कोरिया के साथ हुए समझौते के पुनर्विचार की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। यानि अब नये समझौतों को छोड़ पुराने समझौतों को ठीक करना सरकार की प्राथमिकता बन सकती है। हमें समझना होगा कि इस समझौते से बाहर आने से जो डाटा के मुक्त प्रवाह को अनुमति देने की जो कवायद चल रही थी, उस पर भी विराम लग गया है। गौरतलब है कि इससे भारत के पास यह अवसर है कि विदेशी भुगतान कंपनियों, ई—कॉमर्स कंपनियों और सोशल मीडिया कंपनियों को अपना डाटा भारत में ही रखने के लिए मजबूर किया जाए। यह भारत के डिजिटल इंडिया के सपने को भी साकार करने का काम करेगा।

देखा जाए तो आरसीईपी समझौता प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया, किसानों की आय दोगुनी करना, डिजिटल इंडिया, भारत को मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाना आदि अनेकों सपनों को धूमिल कर देता। अब हम इन मुद्दों पर और जोर—शोर से आगे बढ़ सकते हैं। □□

आरसीईपी पर भारत की 'ना'

धीरे से लगा चीन को जोर का झटका

स्वदेशी जागरण मंच के एक ट्वीट 'से नो टू आरसीईपी' से मुक्त व्यापार समझौता न सिर्फ टल गया बल्कि चीन जैसे देश की टोन भी बदल गई है। बैंकॉक में सदस्य देशों के बीच हेकड़ी के साथ लाबिंग कर रहे चीन को समझौते पर भारत की 'ना' नागवार गुजरी है। कई अन्य देश जो नुकसान की आशंका के बावजूद चुप्पी साधे थे, अब भारतीय निर्णय के साथ कदमताल करते दिख रहे हैं। चीन और मलेशिया को छोड़ बाकी सभी सदस्य देश अब कहने लगे हैं कि इसे अंतिम रूप तभी दिया जाना चाहिए जब किसी भी देश को कोई समस्या न हो और सबका फायदा हो।

दो टूक शब्दों में भारत की 'ना' के बाद आरसीईपी यानी दस आसियान देशों और चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर फिलहाल टल गया है। मालूम हो कि नवंबर 2012 में सदस्य देशों के बीच इस समझौते को लेकर औपचारिक बातचीत शुरू हुई थी। पिछले 7 वर्षों से इसे अमलीजामा पहनाने की कोशिशें चल रही थी। बिंदुवार विषय पर बातचीत कर सहमति के प्रयास लगातार किए जा रहे थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से चीन इस समझौते को लेकर हड़बड़ी दिखा रहा था। 'अमेरिका-चीन ट्रेड वार' गरमाने के बाद चीन को इस समझौते की जरूरत कुछ अधिक ही महसूस होने लगी। इतने बड़े ट्रेड ब्लॉक में शामिल होकर मुक्त व्यापार का फायदा कौन नहीं उठाना चाहेगा? अमेरिकी धौंस के बाद चीन ने इस मंच को एक औजार के रूप में इस्तेमाल करते हुए भारत के बड़े बाजार से भरपाई कर लेने की गरज से उत्सुकता दिखाई। इस बीच भारत के वाणिज्य मंत्रालय के तहत सेंटर ऑफ रीजनल ट्रेड (सीआरटी) के अधिकारियों ने कई उत्पादों के आंकड़े तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर प्रस्ताव के लिए अनुकूल रास्ता तैयार किया। मामले से जुड़े कुछ सलाहकारों व नौकरशाहों ने

चीन के आर्थिक दबदबे को लेकर प्रधानमंत्री ने बाद में जापान का प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ मुलाकात कर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रणनीतिक बातचीत भी की। दोनों नेताओं ने एशिया शिखर सम्मेलन से अलग बैठक कर समुद्री सीमाओं में चीन के बढ़ते दखल और उसके खुल्लम-खुल्ला व्यापार पर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
— स्वदेशी संवाद



जानबूझकर सही तथ्यों को नजरअंदाज कर दिया तथा भारतीय डेयरी उद्योग की भ्रामक रिपोर्ट पेश की, जिससे चीन को और बल मिला।

समझौते को लेकर भारतीय उत्पादकों में पहले से ही बेचैनी थी। आसियान देशों के साथ हुए समझौते के कारण देश के बढ़ते व्यापार घाटा पर चिंता बनी हुई थी। भारतीय हितों को लेकर स्वदेशी जागरण मंच सहित देश के अनेकों संगठनों ने इस समझौते की खुलकर आलोचना की थी। मंच के राष्ट्रीय सहसंयोजक डॉ अश्वनी महाजन ने 'से नो टू आरसीईपी' का ट्वीट किया, जो उत्पादकों, किसानों और विशेष रूप से दुग्ध उत्पादकों के बीच वायरल हुआ। डॉ. महाजन ने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री की प्रेरणा से किसानों की आय दोगुना करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अगर भारत का दुग्ध क्षेत्र खतरे में पड़ता है तो यह केवल सपना ही रह जाएगा। डॉ. महाजन ने रेखांकित किया कि देश में ज्यादातर डेयरी महिलाओं द्वारा संचालित की जाती है, ऐसे में इस समझौते से महिला सशक्तिकरण को भी धक्का लगेगा। डॉ. महाजन ने फसल, पशुधन, मत्स्य पालन और कृषि आयातों के लिए मांग और आपूर्ति के अनुमानों पर नीति आयोग के कार्यकारी समूह की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि वर्ष 2033 तक देश में 292 एमएमटी (मिलियन मेट्रिक टन) दूध की मांग होगी जबकि उत्पादन 300 एमएमटी का होगा। ऐसे में किसी भी देश से दुग्ध आयात का समझौता भारत के हितों के विपरीत होगा। आरसीईपी पर हस्ताक्षर करने से ग्रामीणों में अशांति फैल सकती है और यह एक गलत नीति होगी।

भारत ने बिल्कुल अंतिम समय में



भारतीय हितों को लेकर स्वदेशी जागरण मंच सहित देश के अनेकों संगठनों ने इस समझौते की खुलकर आलोचना की थी।

आसियान देशों के बीच हो रहे क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते से खुद को अलग कर लिया। खुद प्रधानमंत्री ने बैंकों की बैठक में कहा कि चूंकि इस समझौते में भारत के बाजार और किसानों के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किए हैं, इसीलिए भारत ने इससे अलग रहने का निर्णय किया है। इतना ही नहीं चीन के आर्थिक दबदबे को लेकर प्रधानमंत्री ने बाद में जापान का प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ मुलाकात कर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रणनीतिक बातचीत भी की। दोनों नेताओं ने एशिया शिखर सम्मेलन से अलग बैठक कर समुद्री सीमाओं में चीन के बढ़ते दखल और उसके खुल्लम-खुल्ला व्यापार पर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

भारत की चाल से चौंके चीन ने चुप्पी तोड़ते हुए फिर से मिल बैठकर सौहार्दपूर्ण बातचीत कर समझौते के हल हो जाने की आशा व्यक्त की है। चीन के राष्ट्रीय अखबार 'ग्लोबल टाइम्स' ने अपने संपादकीय में लिखा है कि फ्री ट्रेड पर बातचीत पटरी से उतरी नहीं है। और जो थोड़े बहुत सवाल और संदेह रह गए हैं वे आगे साफ कर लिए जाएंगे।

आरसीईपी के 15 अन्य सदस्य

देशों में से 12 देशों (जापान, कोरिया एवं 10 आसियान देश) के साथ भारत का पहले से ही मुक्त व्यापार समझौता हो चुका है, और यह समझौता चालू है। बाकी 4 देशों (आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया एवं चीन) के साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता नहीं हो पाया है। इन सभी 16 देशों के साथ भारत का विदेशी व्यापार घाटा 11500 करोड़ अमेरिकी डॉलर का है। जिसमें से 5400 करोड़ अमेरिकी डॉलर का व्यापार घाटा अकेले चीन के साथ है, और यह व्यापार घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है, जो भारत के लिए एक चिंता का विषय बन गया है। आरसीईपी में भारत के शामिल होने के साथ यह व्यापार घाटा कम होगा अथवा बढ़ेगा, इस बात पर गंभीरता से विचार करना अति आवश्यक है। अभी यह भी साफ नहीं है कि आरसीईपी में शामिल होने के बाद भारत के निर्यात बढ़ेंगे अथवा आयात बढ़ेंगे और किस प्रकार की सहूलियतें भारत को प्राप्त होंगी। चीन अपने देश में आयात संबंधी कई अवरोध खड़े करता है एवं कई प्रकार की सब्सिडी प्रदान करता है, जो पारदर्शी नहीं हैं। क्या इस तरह की समस्याओं को चीन द्वारा हल किया जाएगा, इसका उत्तर भी संतोषजनक रूप से नहीं दिया जा सका। चीन के साथ अन्य देशों की भी विदेशी व्यापार संबंधी समस्याएं हैं।

चीन का आरसीईपी के सदस्य देशों पर अत्यधिक जोर है कि उक्त व्यापार समझौता शीघ्र ही संपन्न किया जाय। क्योंकि, अमेरिका के साथ चीन का व्यापार युद्ध चल रहा है। अतः वह नया बाजार तलाश रहा है, जहां उसके उत्पाद बिक सकें। जबकि भारत चाहता है कि उसका बाजार थोड़ा संरक्षित रहे क्योंकि भारत ने भी अभी तक कई देशों

क्या था यह समझौता

आरसीईपी समझौते में आसियान के दस देशों ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलिपिंस, लाओस और वियतनाम के अलावा छः एफटीए साझेदार चीन, जापान, भारत, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार का रास्ता खोलना है। इसमें कई तरह की रियायतों के अलावा टैक्स के स्तर पर भारी छूट मिलती है। इस समझौते के तहत हर तरह के उद्योग धंधों में ये देश एक दूसरे की सीमा में बिना किसी रोक-टोक के धंधा कर सकेंगे। दुनिया की आधी से कुछ अधिक आबादी और पूरे विश्व की जीडीपी का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा इस समझौते के तहत आने वाला है। □

के साथ मुक्त व्यापार समझौते लागू किए हैं और लगभग इन सभी देशों के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है। अतः भारत अपना हर कदम फूँक-फूँक कर रखना चाहता है। जैसे श्रीलंका के साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौता लागू किया तो उसके लागू होने के बाद रबर एवं मसाले, आदि उत्पादों के मामले में दिक्कतें आनी शुरू हुईं, क्योंकि यह उत्पाद बहुत ही कम कीमतों पर श्रीलंका से भारत में आने लगे और भारत के किसानों के उत्पाद अप्रतिस्पर्धी हो गए। आसियान देशों के

साथ भी भारत ने मुक्त व्यापार समझौते किए परंतु चीन के उत्पाद इन आसियान देशों के माध्यम से भारत में आने लगे। इससे हमारे कृषि एवं उद्योग क्षेत्रों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। न्यूजीलैंड को भी भारत का बाजार चाहिए क्योंकि वहाँ से दूध के 94 प्रतिशत उत्पाद दूसरे देशों को निर्यात किए जाते हैं। भारत में किसानों से दूध 31 रुपए प्रति लीटर खरीदा जाता है वहीं न्यूजीलैंड में 10 रुपए प्रति लीटर दूध खरीदा जाता है। इतना बड़ा अंतर है और अगर दूध का आयात न्यूजीलैंड से भारत में किया

जाता है तो भारतीय किसान कहीं नहीं टिक पाएँगे। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भारत ने विशेष रूप से दो मुद्दे उक्त शिखर सम्मेलन में रखे कि टैरिफ संबंधी प्रतिबंध हेतु वर्ष 2014 को आधार वर्ष बनाए जाने के स्थान पर वर्ष 2019 को आधार वर्ष बनाया जाए। क्योंकि, अन्यथा की स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर भारत में टैरिफ शून्य प्रतिशत हो जाएगा और चीन से इन उत्पादों की भारत में बाढ़ आ जाएगी। दूसरे, स्वतः संरक्षण की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बहुत सारे उत्पाद भारत में आने शुरू हो जाएं और भारत के उद्योगों को किसी प्रकार का संरक्षण ही न रहे।

इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की स्थिति और अन्य देशों की स्थिति में बहुत बड़ा फर्क है। न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया प्राथमिक उत्पादों का निर्यात करते हैं उनके लिए चीन का बाजार बहुत जरूरी है। उन्हें उक्त समझौते से बहुत लाभ होगा। जबकि भारत के साथ ऐसी स्थिति नहीं है। भारत का पूर्व में ही आरसीईपी सदस्य देशों के साथ बहुत बड़ा व्यापार घाटा है, यदि यह घाटा और भी बढ़ता है तो भारत के कृषि एवं उद्योग क्षेत्रों को और अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अतः आज यदि भारत को लग रहा है कि उक्त समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद हम अपने हितों की रक्षा नहीं कर सकेंगे तो हस्ताक्षर न करने संबंधी फैसला एकदम उचित फैसला ही कहा जाना चाहिए। परंतु, आगे आने वाले समय में भारत को अपने कृषि एवं उद्योग क्षेत्रों का तकनीकी रूप से उन्नयन करना ही होगा। क्योंकि, लम्बे समय तक हम संरक्षित वातावरण में नहीं रह सकते। देश के कृषि एवं उद्योग क्षेत्रों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा को झेलने हेतु भी सक्षम बनाना होगा तभी देश मुक्त व्यापार समझौतों का लाभ उठा पाएगा। □□

भारत ने क्यों नहीं किये हस्ताक्षर

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि भारत के इस फैसले से भारतीय किसानों, सूक्ष्म-लघु एवं मझोले उपक्रमों (एमएसएमई) और खासकर डेयरी उत्पाद का हित संरक्षित होगा। स्वदेशी जागरण मंच सहित विभिन्न संगठनों की मांग को देखते हुए प्रधानमंत्री ने भारत की तमाम चिंताओं को बहुत स्पष्ट रूप से रखा। सूत्रों के मुताबिक भारत का इस समझौते से निकलने की खास वजहों में अधिकतर सदस्य देशों के साथ भारत का आयात ज्यादा है निर्यात कम। ऐसे में समझौते के मुताबिक टैक्स घटता है तो भारत का व्यापार घाटा बढ़ेगा। कई देशों ने अभी भी भारत के लिए बाजार सही अनुपात में नहीं खोला है। इस समझौते के परिणाम निष्पक्ष या संतुलित नहीं होने की आशंका अधिक है। भारत में आयात शुल्क बढ़ाने की स्थिति में सुरक्षा की गारंटी मांगी है। चीन के साथ अपर्याप्त अंतर, 2014 को बेस वर्ष माना गया है, जिस पर आपत्ति है। बाजार की पहुंच को लेकर कोई मजबूत भरोसा नहीं मिलना भी वजह है। □

राष्ट्रकृषि दत्तोपंत ठेंगडी (1920—2004)



आरएसएस का ठाणे सम्मेलन, 1972

सन् 1972 में संघ प्रिय, पद्मभूषण श्री पाण्डुरंग शास्त्री अठावले द्वारा महाराष्ट्र के ठाणे में स्थापित तत्व ज्ञान विद्यापीठ के प्रांगण में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की एक बैठक में संघ के सरसंघचालक श्री गुरुजी माधव सदाशिव गोलवलकर जी ने ठेंगडी जी का उल्लेख करते हुए कहा कि 'दत्तोपंत हमारे विचार दाता' हैं। भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक ठेंगडी जी का आह्वान था कि 'श्रम का राष्ट्रीयकरण, राष्ट्र का उद्योगीकरण, उद्योगों को श्रमिकीकरण हो'। दत्तोपंत जी का स्पष्ट मत था कि मार्क्सवादी नारा 'दुनिया के मजदूरों एक हो' के बजाए 'श्रमिक दुनिया को एक करो'। भारतीय स्वभाव और सांस्कृतिक विरासत के अनुरूप ठेंगडी जी का यह परामर्श भारतीय ट्रेड

यूनियन आंदोलन में सिर चढ़कर बोलने लगा तथा धीरे-धीरे वामपंथी मजदूर संगठनों का दायरा सिमटने लगा। आज भारतीय मजदूर संघ भारत का सबसे बड़ा मजदूर संगठन है।

ठाणे में पांच दिन तक चली लंबी बैठक में श्री गुरुजी गोलवलकर ने अपने संबोधन के दौरान विकास की हिंदू अवधारणा के साथ-साथ पश्चिम की सामाजिक आर्थिक संरचना पर भी खुलकर विचार प्रकट किये। अंत में श्री गुरुजी ने भारत के सतत विकास के लिए एक रणनीति तैयार करने के लिए कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एक ऐसा घोषणापत्र होना चाहिए कि देश वर्षों तक एकसाथ उसका पालन करें और लोग उसमें विश्वास करें। तदनुसार ठेंगडी जी ने ठाणे में गुरुजी द्वारा किए गए उन संस्कारों के आधार पर एक रूपरेखा प्रस्तुत की।

वर्षों बाद ठेंगडी जी ने उन विचारों का समर्थन किया कि 'पश्चिमीकरण आधुनिकीकरण नहीं है और पश्चिमी प्रतिमान सार्वभौमिक प्रतिमान नहीं हैं'। पश्चिमी बाजार अर्थव्यवस्था पर ठेंगडी जी द्वारा अधिक विशिष्ट सिफारिशों की गई थीं। उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज, सट्टा व्यापार प्रथाओं जैसे व्युत्पन्न व्यापार, फॉरवर्ड ट्रेडिंग, मुद्रा बाजार आदि का विरोध किया जो कृत्रिम मूल्य वृद्धि और आकस्मिक संकटों के लिए जिम्मेदार हैं। दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानव दर्शन पर काम करने के लिए दत्तोपंत ठेंगडी का अनुसरण करना होगा। गुरुजी, दीनदयाल उपाध्याय और दत्तोपंत ठेंगडी के साहित्य बिना किसी विरोधाभास के एक ही तरंग की लंबाई में चलते हैं।

रिवर्स गियर में साम्यवाद

दत्तोपंत ठेंगडी लोकसभा स्पीकर संजीव रेड्डी के नेतृत्व में संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य थे और 1968 में सोवियत रूस गए थे। रूस से लौटने के बाद उन्होंने घोषणा की



संघ के सरसंघचालक
श्री गुरुजी माधव
सदाशिव गोलवलकर जी
ने ठेंगडी जी का उल्लेख
करते हुए कहा कि
'दत्तोपंत हमारे विचार
दाता' हैं।

— सरोज कुमार मित्र

कि साम्यवाद रूस में पीछे हट (रिवर्स गियर में) रहा है। बाद में सीपीएम सरकार के पश्चिम बंगाल में शासन करने के बावजूद उन्होंने कहा कि वर्तमान समय साम्यवाद के खिलाफ चल रहा है जो कि एक ऐतिहासिक तथ्य साबित हुआ।

ब्लू प्रिंट

टेंगडी जी ने माना कि सत्ता में आने या कार्यान्वयन के चरण के बिना ब्लू प्रिंट तैयार नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने सावरकर की सबसे दिलचस्प और खुलासा करने वाली मिसाल का हवाला दिया, जिसमें लेनिन से ब्लू प्रिंट मांगा गया था। लेनिन ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जो कि रूस के लिए तैयार किया गया, उनका ब्लू प्रिंट भारत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था।

1975 में आपातकाल

जयप्रकाश नारायण (जेपी) ने 1975 में आपातकाल के खिलाफ लड़ने के लिए नानाजी देशमुख को लोक संघर्ष समिति का संयोजक बनाया। नानाजी की गिरफ्तारी के बाद दत्तोपंत टेंगडी ने बीएमएस से इस्तीफा देकर लोक संघर्ष समिति के संयोजक का कार्यभार संभाला। हालांकि पुलिस उनकी तलाश में थी लेकिन टेंगडी जी 9 सितंबर 1975 को अपने अखिल भारतीय दौरे के तहत कोलकाता पहुंचे। टेंगडी जी के साथ रात में एक गुप्त दरवाजे की बैठक में हमने पश्चिम बंगाल और ओडिशा की मौजूदा स्थिति के बारे में चर्चा की। हर जगह डर था और इंदिरा गांधी अपनी जनसभाओं में भारी भीड़ जुटा रही थीं। यह सब सुनने के बाद टेंगडी जी ने हमें बहुत विश्वास के साथ बताया कि इंदिरा गांधी का शासन सत्रह महीने के भीतर समाप्त हो जायेगा। 'क्या यह ज्योतिष

है', मैंने पूछा? 'नहीं', टेंगडी जी ने कहा। आगे उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी तानाशाह बनने की कोशिश कर रही हैं, जबकि उसमें तानाशाह की योग्यता नहीं है। 'वह किसी पर विश्वास नहीं करती और कोई उस पर भरोसा नहीं करता'। अतः यह सरकार विफल हो जायेगी। कोलकाता से लौटने के बाद मुझे कटक में मीसा (मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट) के तहत गिरफ्तार किया गया था और 1977 में सत्रह महीने बाद रिहा किया गया था, जब आपातकाल हटा लिया गया था।

आपातकाल के दिनों में टेंगडी जी रवींद्र वर्मा के साथ पूरे भारत भर में घूमकर रणनीति बनाते रहे। इस दौरान वे मुंबई के जसलोक अस्पताल में जयप्रकाश नारायण से मिले। आपातकाल के दौरान टेंगडी जी के यह साहसिक कार्य की कहानी अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। आपातकाल की निरंतरता के कारण निराश होकर कुछ कार्यकर्ता विशेष रूप से दिल्ली के बैकुंठ लाल शर्मा (जो बाद में सांसद बने) ने इंदिरा गांधी के तानाशाही शासन को उखाड़ फेंकने के लिए हिंसा का सहारा लेने के लिए प्रस्ताव रखा। टेंगडी जी ने इस विचार को अस्वीकार कर दिया और 'क्रांति पर' शीर्षक से एक दस्तावेज प्रस्तुत किया। इस दस्तावेज में विभिन्न देशों में आयोजित हिंसक आंदोलनों और इसके परिणामों का वर्णन किया गया है। अंत में टेंगडी जी ने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण जन आंदोलन ही सफल होता है।

आपातकाल के खिलाफ आंदोलन अहिंसक होते हुए भी व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थ ने बाधा उत्पन्न की। 1976 में जेपी की तबीयत खराब हो गई और उन्होंने टेंगडी जी को किसी को अपने उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तावित करने के लिए कहा। टेंगडी जी ने एस.एम. जोशी के नाम का प्रस्ताव

किया, जो कि पुणे के एक अनुभवी समाजवादी नेता थे। कुछ दिनों बाद चरण सिंह जेपी से मिले और उन्हें अपने उत्तराधिकारी का नाम देने को कहा। (चरण सिंह खुद उत्तराधिकारी बनना चाहते थे।)। इसके बाद चरण सिंह सार्वजनिक बयान के साथ सामने आए कि जनसंघ उनके खिलाफ है। इस तरह के बयान से उस संघि में गलतफहमी पैदा हो गई। हालांकि वे पुलिस निगरानी में थे, लेकिन टेंगडी जी ने चरण सिंह से मिलने के लिए मुंबई से बागपत तक की यात्रा की। टेंगडी जी ने चरण सिंह को समझाया कि उन्होंने जोशी के नाम का प्रस्ताव रखा, क्योंकि जेपी अपने उत्तराधिकारी को सत्ता से बाहर रहने को कहेंगे। इससे पहले कि टेंगडी जी और कुछ बोल सकें, चरण सिंह ने टेंगडी जी को गले लगा लिया और उन्हें बताया कि वह उनके छोटे भाई की तरह हैं। इस तरह के प्रकरण बहुत थे जिसमें टेंगडी जी को राजनीतिक नेताओं को एक साथ लाने का सामना करना पड़ा। एक बार जब इंदिरा गांधी हार गई, तो आपातकाल हटा लिया गया और जनता पार्टी अस्तित्व में आई। इसी के साथ दत्तोपंत जी का मिशन समाप्त हो गया।

राज्यसभा

राज्यसभा (1970-76) के दूसरे कार्यकाल के दौरान टेंगडी जी को चाय पीने के लिए इंदिरा गांधी के निवास पर आमंत्रित किया गया था। वहाँ बातचीत में उनसे पूछा गया कि वे जनसंघ और गुरुजी गोलवलकर दोनों में से किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? टेंगडी जी ने जवाब दिया था 'गुरुजी गोलवलकर' का। हालांकि उन्हें राज्यसभा में उपसभापति पद की पेशकश की गई थी लेकिन टेंगडी जी ने विनम्रता से इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। □□

(लेखक ने टेंगडी जी के अधीन 1968 से 2004 तक विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया है।)

बढ़ते प्रदूषण से निजात के लिए जानना जरूरी है उपयोगी और विनाशकारी मशीनों के बीच का फर्क

राजधानी दिल्ली सहित लगभग पूरे उत्तर भारत की हवा जहरीली हो गई है। टीवी और अखबार लगातार डर का प्रचार करने में लगे हैं। प्रतिदिन का हवा सूचकांक जारी हो रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट और कार्बन फुट प्रिंट को लेकर बड़ी-बड़ी संस्थाएं अकादमिक विमर्श करने में जुटी हैं। अदालतों का रुख भी प्रदूषण को लेकर कड़ा है। एनजीटी लगातार आदेश जारी कर रहा है कि धुआं फैलाने वाले तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाए। खुद प्रधानमंत्री कार्यालय के आला अफसर संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों से हॉट लाइन पर दो टूक बातें कर रहे हैं। राजनीतिक दल एक-दूसरे पर प्रदूषण फैलाने, उसकी अनदेखी करने आदि का आरोप लगाकर अपनी वोट की खेती पक्की कर रहे हैं। जनता भय-संकोच के साथ सांसत में फंसी रोजी-रोटी पर निकल रही है। बड़ी-बड़ी एअर प्यूरीफायर और मास्क बनाने वाली कंपनियां इस धंधे में अपना उल्लू सीधा कर रही हैं।

प्रदूषण को लेकर सारे इफ बट के साथ लगभग सब कुछ हो रहा है, लेकिन प्रदूषण की मूल वजह बताई जा रही है 'पराली' के बारे में कुछ नहीं हो रहा है। पराली क्यों जलाई जा रही है? इस पर कोई बात नहीं हो रही है। चौंकाने वाली एक बात यह भी है कि पराली से संबंधित मुकदमे में दो नामी-गिरामी कंपनियां भी पार्टी बनी हैं। एनटीपीसी और इंडियन पोटाश ने पराली जलाने का अदालत में कड़ा विरोध किया है। एनटीपीसी के उच्च अधिकारिक सूत्रों की मानें तो उनका विरोध इसलिए है कि एनटीपीसी खुद पराली का उपयोग अपने यूनिट में करना चाहती है, जबकि इंडियन पोटाश का तर्क है कि खेतों में पराली जलाने वाले किसान उनकी कंपनी का खाद नहीं खरीदते हैं। खाद की बिक्री कम होना, उनके लिए चिंता की बात है।



कैसी विडंबना है कि एक तरफ चारा के अभाव में पशुओं की मौत हो रही है और दूसरी तरफ उनके निमित्त बने चारे को जलाकर हवा में धुआं भरा जा रहा है। उसी जहरीले धुएं से त्रस्त दिल्ली चीख चिल्ला रही है।

— अनिल तिवारी





पराली की समस्या को ठीक से समझने के लिए हमें अतीत की ओर लौटना होगा। देश में होने वाली पारंपरिक खेती के बारे में भिन्न होना पड़ेगा।

इसलिए ऐसी कंपनियां सरकारी मशीनरी पर लगातार दबाव बनाकर किसानों को ऐसा करने से रोकने की जुगत में जुटी रहती है। राज्यों की सरकारें भी कई बार इन कंपनियों के बहकावे में आकर किसानों को रोकने, उन पर भारी जुर्माना लगाने तथा पराली जलाने के जुर्म में उन्हें जेल भेजने तक की घोषणा करती रही है।

लेकिन इस मुद्दे पर अब किसान भी आक्रामक है। हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में किसानों ने सरकार के कड़े आदेशों का उल्लंघन कर सामूहिक रूप से पराली जलाई है। सोनीपत, करनाल आदि जगहों पर तो बकायदा सड़क जाम कर किसानों ने उग्र विरोध प्रदर्शन भी किया।

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने वादा किया है कि सन 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी। लेकिन वर्तमान समय में किसानों जिस तरफ जा रही है वह रास्ता सकारात्मक नहीं दिख रहा है। सरकार में इस भयावहता को लेकर कोई गंभीर विमर्श अभी तक नहीं दिख रहा है। सवाल केवल पराली जलाने से पर्यावरण को हो रहे नुकसान का ही नहीं है, इससे ऐसी कई और समस्याएं पैदा हो रही हैं जो खेती को विनाश की ओर ले जा रही हैं। डंकल और मोनसैंटो जैसी कंपनियों के अत्याचार से पहले से ही

पटरी से उतर चुकी भारत की पारंपरिक खेती किसानों को आत्महत्या करने तक के लिए बाध्य कर चुकी है। अब पराली जलाए जाने से पशुओं की जान पर भी आफत आ चुकी है। पशुधन का चारा समाप्त प्रायः हैं और करोड़ों पशु भूखे बेबस मरने को मजबूर हैं। सबसे पीड़ादायक बात यह है कि इतना हो-हल्ला मचने के बावजूद भी कृषि मंत्रालय ने इस बात पर विचार ही नहीं किया कि आखिर किसान पराली जलाने के लिए विवश क्यों हैं?

जब तक शासन सत्ता में बैठे लोग इस मूल सवाल पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक मजबूर किसान को ऐसा करने से रोकने का तरीका कैसे दे पाएंगे? नासमझी में तो वही होगा जो अभी हो रहा है। दिल्ली कहेगी कि हरियाणा, पंजाब का धुआं दिल्ली को जहरीला बना रहा है तो हरियाणा-पंजाब कहेगा दिल्ली वोट की राजनीति कर रही है। मसलन सारे रास्ते केवल राजनीति और भाषणबाजी में तलाशे जा रहे हैं। कोई किसानों पर जुर्माना लगा रहा है तो कोई जेल भेज रहा है। कुछ पराली की खरीद योजना शुरू करने का सुझाव दे रहा है। यह सब पिछले कई वर्षों से चल रहा है। होली दिवाली की तरह हर साल अक्टूबर खत्म होते और नवंबर शुरू होते ही राजधानी दिल्ली का यह एक स्थाई विमर्श का रूप ले लिया है।

पराली की समस्या को ठीक से समझने के लिए हमें अतीत की ओर लौटना होगा। देश में होने वाली पारंपरिक खेती के बारे में भिन्न होना पड़ेगा। दो-तीन दशक पहले तक भारत में किसान अपने हाथ से खेती करता था। 95 प्रतिशत घरों में बैल होते थे। खेती की जुताई से लेकर मंडाई तक सारी खेती किसान के जांगर और बैलों के जोर पर होती थी। धीरे-धीरे प्रगति और विकास के नाम पर किसानों का मशीनीकरण कर दिया गया। जुताई से लेकर मंडाई तक अब सारे काम मशीनों से हो रहे हैं। धान और गेहूं की कटाई के लिए अब कंबाइन हार्वेस्टर आ गया है। यह एक ऐसी मशीन है जो फसलों की बालिया काट लेती है और पराली खेतों में ही छोड़ देती है। अब किसान इस पराली का क्या करें? फसल काटने के लिए मजदूरों के अभाव में किसान ने बाध्य होकर कंबाइन से फसल तो कटवा लिया, अब पराली काटने के लिए वह मजदूर कहाँ खोजे? मजदूर मिल भी जाए तो किसान उसकी मजदूरी कहाँ से लाए? पर किसान के सामने दिक्कत यह है कि बगैर पराली हटाए खेत में अगली फसल नहीं कर सकता। ऐसे में किसान को सबसे सुलभ और आसान रास्ता ही दिखता है कि खेत में जहाँ भी पराली है उसमें आग लगा दी जाए। पराली की राख मिट्टी में मिलकर थोड़ा बहुत खाद की भी पूर्ति कर देगी और बिना वजह मजदूरी देने की झंझट से भी बचा जा सकेगा।

जब देश में पारंपरिक तरीके से खेती होती थी, किसान धान और गेहूं अपने हाथ से काटता था और इस तरह की फसलें जड़ से काटी जाती थी। इससे गेहूं और धान के पौधे का एक भी हिस्सा बर्बाद नहीं होता था। गेहूं के ढंडल से भूसा बन जाता था, जो पशुओं का चारा होता था। उसी तरह धान की पराली पशुओं को खिलाने के अलावा

भी कई एक घरेलू कामों में इस्तेमाल की जाती थी।

अब किसान अपने हाथ से कुछ नहीं करना चाहता। हर काम मशीन के अधीन हो गया है। छोटी से छोटी जोत भी अब ट्रैक्टर के भरोसे है। सच्चाई तो यह है कि इस तरह के मशीनीकरण से न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि किसान भी बर्बादी की ओर अग्रसर है। कैसी विडंबना है कि एक तरफ चारा के अभाव में पशुओं की मौत हो रही है और दूसरी तरफ उनके निमित्त बने चारे को जलाकर हवा में धुआं भरा जा रहा है। उसी जहरीले धुएं से त्रस्त दिल्ली चीख चिल्ला रही है।

सवाल है कि कुछ दिनों के लिए गैस चेंबर में तब्दील होती देश की राजधानी दिल्ली और चारा के अभाव में पशुओं की भूख से होने वाली मौत से कैसे बचा जाए? साधन संपन्न लोग इस मौसम में अब दिल्ली से बाहर रहने का पहले ही कार्यक्रम बना लेते हैं, वहीं इन दिनों में विदेशी पर्यटकों की आवक कम होती जा रही है। लेकिन आमजन तो रोज लड़ने और इसी में रहने को अभिशप्त है। इसी तरह भूसा के अभाव में किसानों ने पशुओं को आवारा छोड़ना शुरू कर दिया है। कई बार तो यह आवारा पशु अपनी भूख मिटाने के लिए खेतों में खड़ी फसलों पर मुंह मारते हैं, यह मार भी किसानों पर ही पड़ती है। आवारा पशुओं

इसी तरह भूसा के अभाव में किसानों ने पशुओं को आवारा छोड़ना शुरू कर दिया है। कई बार तो यह आवारा पशु अपनी भूख मिटाने के लिए खेतों में खड़ी फसलों पर मुंह मारते हैं, यह मार भी किसानों पर ही पड़ती है।

का आतंक कई क्षेत्रों में ऐसा हो गया है कि किसान रात-रात भर जागकर रखवाली करते हैं। इससे उनकी कार्य क्षमता तथा सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। पिछले पांच साल के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में हृदय रोगियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। सांस तथा फेंफड़े की बीमारी ने भी पैर पसारा है।

इन सारी समस्याओं की जड़ से लाख टके का सवाल है कि इसका हल क्या है? क्या हम पुराने दिनों की ओर लौट चलें? क्या उस पद्धति को फिर से अपनाएं, जिसमें बैलों से खेती होती थी? एक मिनट के लिए अगर सरकार और समाज ऐसा तय भी कर ले, तो क्या लोग फिर हाथ से खेती करने को तैयार होंगे? शायद नहीं। मशीनों को सिरे से छोड़ने की न तो कोई वकालत कर सकता है और ना ही आदत छोड़

चुके किसान इसके लिए तैयार होंगे। लेकिन समय आ गया है कि हम सच्चे मन से उपयोगी और विनाशकारी मशीनों के बीच के फर्क को समझें। हित और अहित के लिए लामबंद होवें। समाज को भी इसके लिए जागृत करें। सोंचिए आखिर ऐसी किसी मशीन से क्या फायदा जो मनुष्यों के लिए अनाज निकाल दें लेकिन पशुओं का चारा खेतों में छोड़ दे, जिसे बाद में जलाना पड़े। सरकार को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। सरकार पशुधन के लिए खतरनाक ऐसी मशीनों पर कानून बनाकर अंकुश लगाए तथा ऐसी मशीनों के लिए पहल करें जो फसलों को जड़ से काटती हो।

अभी हमारे देश के कई हिस्सों में जैसे कि मध्य प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक के किसान मशीन के साथ-साथ पशुधन का उपयोग करते हैं। यही तरीका उत्तर पश्चिम के लोग क्यों नहीं अख्तियार करते? क्या सरकार के स्तर पर इसके लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए जाने चाहिए? पर दुर्भाग्य है कि प्रगति की अंधी दौड़ में इसकी फिक्र ना के बराबर है और तो और हमारे कृषि वैज्ञानिक भी इस विनाशकारी प्रक्रिया पर किनारा किए हुए हैं। हमारी इसी उदासीनता का फायदा बड़ी-बड़ी कंपनियां उठा रही है। आम लोगों में डर पैदा कर वे अपना माल बेचकर मुनाफा बढ़ाने में जुटी है। □□

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका आर्थिक सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते हैं। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवेदना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते हैं तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

संपादक, स्वदेशी पत्रिका

‘धर्मक्षेत्र’, सेक्टर-8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली-110022

पश्चिमी देशों का मोह छोड़

छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहन जरूरी

सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन का बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार की रणनीति है कि ब्याज दर में कटौती की जाए, जिससे कि उपभोक्ता के लिए ऋण लेकर खपत करना आसान हो जाए। जैसे ऋण लेकर कार खरीदने को वह उद्यत हो। अथवा न्यून ब्याज दर से प्रेरित होकर उद्यमी ऋण लेकर फैक्ट्री लगाए जिससे की रोजगार भी उत्पन्न हो और उत्पादन भी बढ़े और हमारे आर्थिक विकास को गति मिले। लेकिन उद्यमी के लिए ब्याज दर का विषय बाद में आता है। उद्यमी के लिए पहला विषय होता है कि बाज़ार में माल की मांग है या नहीं। यदि बाज़ार में माल की मांग होती है तो वह येनकेन प्रकारेण पूँजी की व्यवस्था कर फैक्ट्री लगाता ही है। इसके विपरीत यदि बाज़ार में मांग नहीं है तो वह ब्याज दर कम होने पर भी ऋण नहीं लेता है क्योंकि फैक्ट्री लगाकर प्रॉफिट तभी हासिल किया जाता है जब उत्पादित माल को बेचा जा सके। यदि ब्याज दर कम हो और आप उसके लालच में फैक्ट्री लगा लें लेकिन माल बिके नहीं तो वह न्यून ब्याज दर निरर्थक हो जाता है। हम देख रहे हैं कि पिछले दो वर्षों में रिज़र्व बैंक ने कई बार ब्याज दरों में कटौती की है लेकिन अर्थव्यवस्था की विकास दर लगातार गिरती ही जा रही है। यह इस बात का प्रमाण है कि ब्याज दर को न्यून करके हम आर्थिक विकास को हासिल नहीं कर सकते हैं। इसके विपरीत यदि बाज़ार में मांग हो और उद्यमी फैक्ट्री लगाने को उद्यत हो तो न्यून ब्याज दर उसे अवश्य ही प्रेरित करती है कि वह छोटे के स्थान पर बड़ी फैक्ट्री लगाए और 10 के स्थान पर 20 कर्मियों को रोजगार दे। अतः मुख्य बात बाज़ार में मांग का होना है।

प्रश्न है कि इस समय बाज़ार में मांग क्यों नहीं उत्पन्न हो रही है। मांग उत्पन्न होने के लिए आम आदमी के पास क्रय शक्ति होनी चाहिए। किसान अथवा मध्यम वर्गीय कर्मियों के पास आय होनी चाहिए जिससे कि वे बाज़ार में जाकर टेलीविज़न अथवा बाइक खरीदें। बाज़ार में मांग न होना इस बात की तरफ संकेत करता है कि आम आदमी के पास क्रय



विकसित देशों के बड़े-बड़े उद्यमियों और बिल्डरों की चकाचौंध से सरकार को भटकना नहीं चाहिए। जब तक सरकार अपने आम आदमी के रोजगार की और ध्यान नहीं देगी, तब तक देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होने की संभावना कम ही है।
— डॉ. भरत भुनझुनवाला



शक्ति नहीं है। प्रश्न है कि यह क्रय शक्ति गयी कहाँ? मेरा मानना है कि नोटबंदी और जीएसटी ने आम आदमी की जीविका पर भारी चोट की है। नोटबंदी के कारण तमाम छोटे उद्यमियों का धंधा चौपट हो गया है। नोटबंदी के बाद एक ओला के ड्राइवर से बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि वह तीस वर्षों से 3-4 कर्मियों को रोजगार देते थे। साड़ियों पर एम्ब्रॉयडरी इत्यादि करा कर उन्हें बेचते थे। लेकिन नोटबंदी से उनके क्रेताओं ने माल खरीदना बंद कर दिया। उन्हें अपने कर्मियों को बर्खास्त करना पड़ा और स्वयं ओला की ड्राइवरी करने को मजबूर हुए। मेरा अनुमान है कि इस प्रकार के तमाम उदाहरण हैं जिसके कारण आम आदमी की क्रय शक्ति कम हो गयी है और बाज़ार में मांग कम हो गयी है। जीएसटी का प्रभाव भी कुछ इसी प्रकार हुआ है। पूरे देश का बाज़ार एक हो गया है। इसका विशेष लाभ बड़े उद्यमियों को हुआ है। हरिद्वार के एक परदे बनाने वाले ने बताया कि पूर्व में उसके बनाए परदे बिकते थे क्योंकि सूरत के परदे आने में सरहद पर क्रय कर का प्रपंच रहता था। जीएसटी लागू होने के बाद सूरत के परदे बेरोक टोक उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे हैं और उसका धंधा दबाव में आ गया है।

सरकार की सोच है कि विकसित देशों की तरह हम भी आधुनिक बड़े बड़े कारखाने लगायें। इस नीति को लागू करने के लिए नोटबंदी और जीएसटी को लागू किया गया है। इस कारण छोटे उद्यमी दबाव में आ गए हैं, लोगों को रोजगार कम मिल रहा है, आम आदमी की क्रय शक्ति कम हो गयी है, बाज़ार में मांग नहीं है और बड़े उद्यामी भी निवेश करने को उद्यत नहीं हैं।

सरकार की सोच यह भी है कि छोटे उद्यमियों को 10 वर्ष मात्र तक छूट दी जाए जिसमें ब्याज दर कम

सरकार का कहना है कि जिस प्रकार एक पौधा सदा छोटा नहीं रहता बल्कि समय अनुसार उसे बड़े पौधे में बढ़ना चाहिए उसी प्रकार छोटे उद्यम को सदा छोटा नहीं रहना चाहिए।

होती है अथवा कुछ कानूनों से मुक्ति मिलती है। सरकार का कहना है कि जिस प्रकार एक पौधा सदा छोटा नहीं रहता बल्कि समय अनुसार उसे बड़े पौधे में बढ़ना चाहिए उसी प्रकार छोटे उद्यम को सदा छोटा नहीं रहना चाहिए। यदि वह बड़ा नहीं होता तो उसका छोटे उद्यम का दर्जा दस वर्ष बाद समाप्त कर देना चाहिए। मेरा मानना है कि पौधे से तुलना करना उचित नहीं है। सही तुलना है धावक से। हर व्यक्ति की दौड़ करने की क्षमता अलग अलग होती है। जो व्यक्ति कम तेज़ी से दौड़ता है उसे दौड़ से सदा के लिए बाहर नहीं करना चाहिए। वह रिक्शा चला सकता है यद्यपि वह उतना तेज़ नहीं चला सकेगा जितना दूसरा रिक्शाचालक चलाता है। तमाम ऐसे उद्यमी हैं जिनकी क्षमता छोटे उद्यम को चलाने तक सीमित है। हम यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि हर छोटा उद्यम समय क्रम में बड़ा हो ही जाएगा। लेकिन सरकार की सोच है कि इस प्रकार के छोटे उद्यम को समाप्त कर दिया जाए। सरकार की इस सोच के कारण देश में आम आदमी का रोजगार कम हो रहा है और बाज़ार में मांग कम हो रही है और निवेश भी कम हो रहा है।

सरकार की यह सोच भी है कि

चीन द्वारा 80 और 90 के दशक में अपनाई गयी नीति को हम अपनाएं। लेकिन आज की परिस्थितियों में मौलिक अंतर है। उस समय विकसित देशों में नए नए तकनीकी आविष्कार हो रहे थे जैसे विंडोज का सॉफ्टवेयर, लैपटॉप अथवा इन्टरनेट। इन नयी तकनीकी आविष्कारों के बल पर विकसित देशों की आय बढ़ रही थी और वे चीन से सस्ता माल खरीद रहे थे। आज विकसित देशों के पास इन्टरनेट जैसे आविष्कार कम ही उपलब्ध हैं। उनकी विकास दर भी दबाव में है इसलिए उनकी मांग कम बन रही है। दूसरी बात यह कि रोबोट और आटोमेटिक मशीनों के आविष्कारों से आज विकसित देशों में माल का उत्पादन भी लाभप्रद हो गया है। जैसे पूर्व में फुटबॉल बनाने के लिए कर्मियों की भारी संख्या में जरूरत पड़ती थी इसलिए फुटबॉलका उत्पादन चीन में होता था। आज यदि रोबोट के द्वारा फुटबॉल बनायी जाने लगे तो उसका उत्पादन विकसित देशों में हो सकता है। इस कारण आज विकसित देशों द्वारा भारत जैसे देशों से माल का आयात कम ही किया जा रहा है। आज हम चीन द्वारा पूर्व में अपनाई गयी नीति को अपनाकर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं।

सरकार को चाहिए कि अपनी नीतियों में मौलिक परिवर्तन करें अन्यथा स्थिति बिगड़ती जायेगी। मूल बात यह है कि छोटे कर्मियों, छोटे किसानों और छोटे बिल्डरों सबको संरक्षण दिया जाए। इनके द्वारा रोजगार अधिक बनते हैं और इन रोजगारों से ही अर्थव्यवस्था में मांग बनती है। विकसित देशों के बड़े बड़े उद्यमियों और बिल्डरों की चकाचौंध से सरकार को भटकना नहीं चाहिए। जबतक सरकार अपने आम आदमी के रोजगार की और ध्यान नहीं देगी तब तक देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होने की संभावना कम ही है। □□

ऑनलाईन खरीददारी से छोटे दुकानदारों को खतरा

देश में गत कुछ वर्षों से जिस प्रकार ऑनलाईन व बड़े बड़े मॉल में दुकानदारी का फैलाव चल निकला है। उससे देश में 5 करोड़ फुटकर व छोटे दुकानदारों के हित खतरे में पड़ते नजर आ रहे हैं। इन दुकानदारों पर अपने परिवार के 15 करोड़ लोगों के जीवन निर्वाह का भार भी है। देश में बेरोजगारी की समस्या को हल करने में इस क्षेत्र का अभूतपूर्व योगदान सदैव रहा है, परन्तु जिस प्रकार कुछ विदेशी कंपनियां इस क्षेत्र में घुस गई हैं, उससे छोटे दुकानदारों को बहुत बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। रही-सही कसर बड़े-बड़े मॉल में बढ़ती दुकानदारी ने पूरी कर दी है। लोग इस परेशानी के लिए नरेन्द्र मोदी सरकार को दोष देने लगे हैं और राजनीतिक विपक्ष इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने में जुट गये हैं। व्यवसाय में देश में मंदी की स्थिति है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। उसके लिए अकेले मोदी सरकार को दोष दिया जा रहा है। सरकार किसी भी राजनीतिक दल की होती सभी को मंदी की यह स्थिति झेलनी ही पड़ती। अभी तक कोई भी यह समझ नहीं सका है कि व्यापार के कमजोर पड़ने के पीछे और क्या कारण हो सकते हैं? परन्तु इतना जरूर माना जा सकता है कि ऑनलाईन व्यवसाय ने देश के स्थापित फुटकर व्यापार को हिला कर रख दिया है। इसलिए प्रत्येक आम व खास जन को चेत जाना चाहिए, अन्यथा संपूर्ण समाज को बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। वर्तमान नयी जनसंख्या (युवा पीढ़ी) अपनी जरूरत का अधिकतम सामान ऑनलाईन ही क्रय कर रही है। जिससे जाने अनजाने में अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी हम सब लोग मार रहे हैं।

इस समय भारत में अमेजन कंपनी कुल ऑनलाईन बाजार का 30 प्रतिशत व्यापार अकेले कर रही है जबकि फ्लिपकार्ट 20 प्रतिशत माल बेच रही है। अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि कम से कम 10 लाख रुपये के मूल्य का माल प्रति सेकंड भारत में खरीदा जा रहा है, अर्थात् प्रति मिनट 6 करोड़ रुपये यानी 360 करोड़ रुपये प्रति घंटा और एक दिन में चार



महात्मा गांधी भी यही कहा करते थे कि अपने आवयकताओं की पूर्ति स्थानीय उत्पादों के द्वारा करनी चाहिए। उनकी 150वीं जयंती पर हम सभी को महात्मा गांधी की यह शिक्षा अवश्य मान लेनी चाहिए। उनके प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी।

— डॉ. सूर्य प्रकाश अग्रवाल



हजार करोड़ रुपये की बिक्री हो रही है। एक वर्ष में 15 लाख करोड़ रुपये की बिक्री ऑनलाईन हो रही है और जिसका 50 प्रतिशत यही दो कंपनियां ही कर रही हैं।

पहले यह पैसा बाजार में आता था तथा एक रोटे-रान् स्थपित होता था परन्तु अब यह पैसा ऑनलाईन बिक्री में ही जा रहा है। कहा यह जाता है कि यह बिक्री इसलिए होती है कि अक्सर ज्यादा बिक्री वाली चीजों पर सब्सिडी दे रही है। अमेजन भारत की नम्बर एक भाँपिंग बेवसाइट बन चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि यदि ऑनलाईन बिक्री की यही गति रही तो आगामी पांच वर्षों में ही घरेलू छोटे-छोटे फुटकर दुकानदार अपने व्यापार से हाथ धो बैठेंगे। फिर यही ऑनलाईन वाली कंपनियां अपनी मर्जी से रेट लेगी, तब भाग्य हमारे पास माल खरीदने के लिए पैसा ही नहीं होगा और हमें इस बात का कडवा अहसास होगा कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी।

एक ग्राहक अथवा परिवार के लोग जब कोई सामान क्रय के लिए बाजार जाता है तो केवल एक वस्तु की ही बिक्री नहीं बढ़ती, अपितु घर से बाजार तक यातायात के साधनों को किराया मिलता है, बाजार में घूमना-फिरना परिवार के लोगों के सेहत के लिए अच्छा होता है। वहां हल्का अथवा भारी खाने-पीने की चीजें प्रयोग की जाती हैं, इससे छोटे-छोटे स्ट्रीट साइड खड़े ठेले वालों की दुकानदारी चलती है। परिवार के लोगों की आत्मीयता दुकानदार से बनती चली जाती है। जिससे समाज में कटुता खत्म होकर भाईचारा का निर्माण होता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से एक ग्राहक अथवा उसके परिवार के लोगों का बाजार तक आने जाने में कई व्यवसायों को लाभ पहुंचता है।

किसी जमाने में ब्रिटेन से ईस्ट



इंडिया कंपनी व्यापार के बहाने से भारत में घुसपैठ करने में सफल हो गई थी जिसका प्रभाव भारत के लोगों पर 250 वर्षों तक आर्थिक, राजनैतिक व सामाजिक आदि सभी क्षेत्रों में देखने को मिला और उसने भारत की जनता का जमकर भोशण किया। अब इसी प्रकार की कंपनियों की संख्या हजारों में पहुंच गई है। वैश्वीकरण व उदारीकरण के नाम पर विदेशों से बड़ी संख्या में माल का आयात किया जाता है। यही कंपनियां भारतीय नवधनाड्य व मध्यम आय वर्ग के लोगों को 100-200-500 रुपये की बचत के लालच में अपनी ओर खींच रही है, जिससे भारत में फुटकर व्यापार क्षेत्र के भविष्य पर दांव लग गया है। हजारों करोड़ रुपया लाभ के रूप में कमाने वाली इन ऑनलाईन कंपनियों ने देश में आई बाढ़ से त्रस्त कितने व्यक्तियों की सहायता की। देश में होने वाले तीज त्यौहार का भारत में फुटकर व्यापार क्षेत्र पर व्यापक प्रभाव है। उनके लिए कितना दान व चंदा दिया जाता है, जबकि आम दुकानदार सुबह से सांय तक पता नहीं कितने लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से दान व सहायता नित्य प्रति देता रहता है। स्थानीय दुकानदार स्थानीय समस्याओं को दूर करने में सदैव तत्पर रहता है जबकि ऑनलाईन कंपनियां हमारे पैसे को विदेश में ले जाती हैं और धीरे धीरे हम विदेशी संस्कृति व चीजों के गुलाम होते चले जाते हैं।

भारत की सरकार ने विदेशी कंपनियों को आगाह किया है कि ई-कामर्स प्लेटफार्म का प्रयोग आक्रामक प्राइसिंग और भारी भरकम डिस्काउंट के लिए न करें।

भारत की सरकार ने विदेशी कंपनियों को आगाह किया है कि ई-कामर्स प्लेटफार्म का प्रयोग आक्रामक प्राइसिंग और भारी भरकम डिस्काउंट के लिए न करें। सरकार छोटे खुदरा कारोबार को खत्म नहीं होने देगी क्योंकि यह क्षेत्र काफी संवेदनशील है। ऑनलाईन वाली कंपनियां बड़ी मात्रा में पूंजी का प्रयोग करके डिस्काउंट पर सस्ते उत्पाद खरीद लेती हैं फिर अधिक डिस्काउंट देकर छोटे दुकानदारों को व्यापार से बाहर करने में सक्षम होती हैं। जब से एफडीआई की अनुमति इन ऑनलाईन व्यापार में लगी कंपनियों को मिली है तभी से विदेशी पूंजी का प्रायोग करके कंपनियां क्रेताओं को आकर्षक ऑफर के जरिए ग्राहकों को आकर्षित कर रही हैं। केन्द्र सरकार में रेल, वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के तत्वावधान में आयोजित इंडिया इकोनॉमिक समिट में 3 अक्टूबर 2019 को नई दिल्ली में अपने संबोधन में कहा कि इस संबंध में भारतीय व विदेशी कंपनियों से लम्बी चर्चा की गई है। अमेरिकी कंपनियों से भी चर्चा हुई है तथा इस फुटकर व्यापार क्षेत्र को लेकर भारत के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। भारत ने इस क्षेत्र के लिए एक स्थायी और उम्मीद के अनुसार रेगुलेटरी ढांचा तैयार किया है। गोयल ने अमेरिकी वाणिज्य मंत्री विलबर रॉस की उपस्थिति में स्पष्ट रूप से कहा कि

हमारी घरेलू राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के परिप्रेक्ष्य में और स्मॉल रिटेल पर आश्रित 12-13 करोड़ लोगों को ध्यान में रखते हुए यह क्षेत्र हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दे 1 में 5-6 करोड़ छोटी दुकानें हैं जो लोगों को रोजगार उपलब्ध करवा रही हैं। इसलिए यह विषय हमारे लिए बहुत ही संवेदनशील हो जाता है। इसी कारण से सरकार ने मल्टी ब्रांडरिटेल सेक्टर में एफडीआई की सीमा 49 प्रतिशत ही रखी है। गोयल ने आगे कहा कि भारतीय कानून की मूल भावना छोटे दुकानदारों को संरक्षण देने की है और उम्मीद है कि विवेक का हर दे 1 अपने लोगों के लिए रोजगार और उनके जीवन यापन के लिए कामकाज के हितों का ध्यान रखता है। इस अवसर पर रॉस ने कहा कि वह भी छोटे दुकानदारों, किसानों और अन्य समूहों की राजनीतिक संवेदनशीलता को समझते हैं। ई-कामर्स ग्राहकों के लिए सस्ते उत्पाद उपलब्ध कराने का एक

माध्यम है और भारत जैसे दे 1 जहां लोगों की आय काफी कम है, वहां लोगों को अधिक दाम देने पड़ रहे हैं। यह देखना जरूरी है कि चीजें कितनी तेजी से बदलती हैं। रॉस के अनुसार भारत में अमेजन के निवेश में कमी आई है।

भारत की कोविड 19 है कि वर्ष 2024 तक पांच ट्रिलियन डॉलर या वर्ष 2030 तक 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाय तथा अगले 30 वर्षों तक 9-10 प्रतिशत की विकास दर भी सुनिश्चित हो जाये। भारतीयों का कर्तव्य है कि भविष्य में खतरे को पहचानते हुए स्वयं के द्वारा ऑनलाईन खरीददारी बंद कर देनी चाहिए अथवा बहुत कम कर देनी चाहिए। उधर छोटे छोटे दुकानदारों के द्वारा वे सभी सुविधाएँ भी अपने ग्राहकों को देनी चाहिए जिसके लिए ग्राहक उन कम्पनियों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। सभी लोग अपने आसपड़ोस की दुकान, छोटे व्यापारी, ठेले वाले, रेडी वाले व खोमचे वालों से सामान

खरीदें इससे बाजार में मंदी का दौर भी कम हो सकेगा और एक गरीब फुटकर दुकानदार आदमी के घर में भी आय आती दिखेगी जिससे वह भी अपने घर तय्यार मना सकेगा। अपनी जरूरत का सामान ऑनलाईन अथवा बड़े बड़े मॉल से न खरीद कर पास ही फुटपाथ पर बैठे व छोटे दुकानदारों से खरीदारी करें जिससे बाजार में पैसों का रोटेयन बन सके। राष्ट्रभक्ति दिखाते हुए हम सभी भारतीयों का कर्तव्य बन जाता है कि स्थानीय स्तर पर ही बनी व उत्पादित वस्तुओं को ही स्थानीय स्तर पर खरीदें। महात्मा गांधी भी यही कहा करते थे कि अपने आवश्यकताओं की पूर्ति स्थानीय उत्पादों के द्वारा करनी चाहिए। उनकी 150 वीं जयन्ती पर हम सभी को महात्मा गांधी की यह शिक्षा अवश्य मान लेनी चाहिए। उनके प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। □□

लेखक सनातन धर्म महाविद्यालय मुजफ्फरनगर, 251001 (उ.प्र.), में वाणिज्य विषय में एसोसियेट प्रोफेसर के पद व महाविद्यालय के प्राचार्य पद से अवकाश प्राप्त हैं व तथा स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर छिपाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि "स्वदेशी पत्रिका" के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :-

स्वदेशी पत्रिका	वार्षिक	आजीवन
हिन्दी	150 रुपए	1500/- रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/- रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. **602510110002740, IFSC : BKID-0006025 (Ramakrishnapuram)**

में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजें।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर-8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-22

अधिक जानकारी के लिए देखें :

<http://swadeshionline.in/>

कृषि सब्सिडी से विकास मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं

सघन खेती ने पिछले कुछ दशकों में न केवल कृषि संकट को और गहरा किया है बल्कि प्राकृतिक संसाधनों को भी इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। बताया जाता है कि खेती का यह तरीका 25 फीसदी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। दुनिया भर में यह विश्वास अपनी जड़ें जमा रहा है कि जलवायु परिवर्तन के पीछे खेती एक प्रमुख कारण है। इसलिए इस बात की मांग बढ़ रही है कि खेती के तौर-तरीकों में बदलाव लाया जाए। साथ ही सुरक्षित और जैविक भोजन के उत्पादन की मांग जोर पकड़ रही है।

फूड एंड लैंड यूज कोएलिशन (एफओएलयू) 2019 दुनिया भर के वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों का एक संगठन है, इसका मानना है कि सस्ते भोजन का अप्रत्यक्ष मूल्य इंसान की सेहत, प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण को चुकाना पड़ता है। इसकी रिपोर्ट ने आगाह किया है कि अगर चीजें ऐसी चलती रहीं तो आधी दुनिया 2030 तक कुपोषण का शिकार हो जाएगी। इस रिपोर्ट में कृषि संकट के पीछे कारणों का अनुमान लगाने के अलावा उन दस उपायों की सूची भी दी गई है जिन्हें अपनाए जाने की आवश्यकता है।

अल्प पोषण या छिपी हुई भूख इस कृषि संकट का सबसे दुखद परिणाम है लेकिन इसके कारण होने वाला प्राकृतिक संसाधनों का विनाश और पर्यावरणीय संकट भी किसी नरसंहार से कम नहीं होंगे। इस रिपोर्ट के अनुसार एक साल में भोजन उगाने में करीब 700 अरब डॉलर खर्च किए जाते हैं। चूंकि इसमें हर सब्सिडी को शामिल करना असंभव है इसलिए माना जा सकता है कि यह राशि इससे भी कहीं ज्यादा होगी।

लेकिन इससे पहले कि आप किसी नतीजे पर पहुंचे आपको बता दें कि ये सभी सब्सिडियां या छूट किसानों तक नहीं पहुंचतीं। उन्हें डायरेक्ट इनकम सपोर्ट के तौर पर इनका बस एक छोटा सा अंश भर ही मिलता है।



अनिवार्य रूप से शुरू में यह सुनिश्चित करना होगा कि कृषि विश्वविद्यालय अपने अनुसंधान कार्यक्रमों को इस तरह से बनाएं जो रासायनिक चीजों को इस्तेमाल न करने पर आधारित हों। इसके लिए मानसिकता परिवर्तन जरूरी है जिसमें कुछ समय भी लग सकता है लेकिन निश्चित तौर पर यह असंभव नहीं है।
— देविन्दर शर्मा



विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के कृषि पर पहले 10 वर्षों के समझौतों पर तैयार एक रिपोर्ट के प्रमुख लेखक के रूप में मैंने अनुमान लगाया था कि इनमें से 80 प्रतिशत से अधिक सब्सिडी वास्तव में कृषि व्यवसाय करने वाली कंपनियों के खाते में गई थी। उस समय डब्ल्यूटीओ ने अंदाजा लगाया था कि अमीर देशों ने लगभग 360 अरब डॉलर सब्सिडी के रूप में दिए थे। इस रिपोर्ट को 2005 के हांगकांग के मंत्रीस्तरीय सम्मेलन में पेश किया गया था।

इस सब्सिडी का अधिकांश भाग निर्यात आधारित कृषि के लिए था जिसके लिए सघन खेती को अपनाया गया। इसका दुष्प्रभाव मृदा स्वास्थ्य पर पड़ा, भूजल दूषित हुआ, वर्षा वनों को काटकर उनकी जगह पाम ऑयल के लिए ताड़ के पेड़ लगाए गए, पशुपालन हुआ, जैव-ईंधन वाली फसलें उगाई गईं, औद्योगिक स्तर पर जानवर पाले गए जिससे न केवल पर्यावरण प्रदूषित हुआ, जैव विविधता पर चोट पहुंची बल्कि इससे अस्वास्थ्यकर भोजन की पैदावार हुई।

उन्होंने कहा, 'हमें इन सब्सिडियों को सकारात्मक उपायों में बदलना होगा।' इसलिए चुनौती विशाल है लेकिन सुरक्षित भोजन उगाने की सही दिशा में उठाए गए छोटे कदमों से जल्द ही जमीनी बदलाव सामने आएंगे।

हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से अपील की है कि वे रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कम करना शुरू कर दें लेकिन वैज्ञानिक विरादरी का मानना है कि इससे हरित क्रांति से जो लाभ मिले रहे हैं वे खतरे में पड़ जाएंगे। लेकिन नेचर (मार्च 2018)



सवाल है कि पंजाब के किसानों को प्रोत्साहन पैकेज क्यों नहीं दिया जा सकता ताकि वे धान की जगह कम पानी की खपत करने वाली फसलों को उगाने की प्रेरणा ले सकें?

में छपे एक शोध पत्र के अनुसार, इसके विपरीत चीन ने उर्वरकों का प्रयोग 15 प्रतिशत कम करके चावल, गेहूं और मक्के की उत्पादकता में औसतन 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है।

लेकिन उल्लेखनीय बदलाव तब हुआ जब चीन ने बरसों एक मिशन के तहत काम करके 14,000 वर्कशॉप आयोजित की, 65,000 नौकरशाहों, तकनीकी विशेषज्ञों और 1,000 शोधकर्ताओं को इस काम में लगाया। इस बीच चीन ने यह भी ऐलान किया है कि वह 2020 तक उर्वरक और कीटनाशकों की सब्सिडी में बढ़ोतरी की दर शून्य कर देगा। कोई कारण नहीं है कि भारत इससे प्रेरणा लेकर राज्य कृषि प्रसार तंत्र को जैविक खेती की ओर न मोड़ सके, साथ ही साथ हर साल उर्वरक सब्सिडी कम करने के लिए ठोस कदम भी उठाए।

इसी तरह जब पंजाब और हरियाणा पानी की बहुत अधिक खपत

करने वाली फसलों को उगाने की वजह से गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत ने उन किसानों की मदद के लिए 50 करोड़ ऑस्ट्रेलियन डॉलर वाला एक फंड बनाया है जो खेती में पानी के इस्तेमाल कम करने का काम कर रहे हैं।

सवाल है कि पंजाब के किसानों को इसी तरह का प्रोत्साहन पैकेज क्यों नहीं दिया जा सकता ताकि वे धान की जगह कम पानी की खपत करने वाली फसलों को उगाने की प्रेरणा ले सकें? अगर उद्योगों को 1.45 लाख करोड़ का प्रोत्साहन दिया जा सकता है तो कोई कारण नहीं दिखाई देता कि किसानों को ऐसा प्रोत्साहन क्यों नहीं मिल सकता।

लेकिन अनिवार्य रूप से शुरू में यह सुनिश्चित करना होगा कि कृषि विश्वविद्यालय अपने अनुसंधान कार्यक्रमों को इस तरह से बनाएं जो रासायनिक चीजों को इस्तेमाल न करने पर आधारित हों। इसके लिए मानसिकता परिवर्तन जरूरी है जिसमें कुछ समय भी लग सकता है लेकिन निश्चित तौर पर यह असंभव नहीं है।

इसके साथ, जरूरी है कि कृषि के लिए मिलने वाला बजटीय समर्थन भी पर्यावरणोन्मुखी हो। विश्व स्तर पर एफओएलयू रिपोर्ट प्रयास कर रही है कि कम से कम 500 अरब डॉलर की कृषि सब्सिडी धारणीय कृषि, गरीबी उन्मूलन और पारिस्थितिक बहाली पर खर्च की जाए। निश्चित रूप से यह मुश्किल काम है लेकिन नामुमकिन नहीं।

(लेखक प्रख्यात खाद्य एवं निवेश नीति विश्लेषक हैं, ये उनके निजी विचार हैं)

<https://www.gaonconnection.com/samvad/agricultural-subsidies-have-to-cause-development-instead-of-destruction-46512?fbclid=IwAR1JpEy11Y3MGm1ulsaF6zb-aA6iR2Vu5t17Sp1adcF4aYHaF2Q1rjWFGU>

कहां गुम हो गये हैं पोखर-तालाब



पोखर और बावड़ी अपने आगोश में बरसाती जल को समेट कर जहां एक और प्रकृति तथा जीव जंतुओं को वर्ष पर्यंत अपने जल से संतुष्टि प्रदान करेंगे, वहीं दूसरी ओर वर्षा के जल को बहने से रोककर भूगर्भ के जल को भी संरक्षण तथा संवर्धन प्रदान करने का कार्य करेंगे जिससे भूगर्भ जल का स्तर भी ऊपर उठेगा तथा पानी की समस्या से कुछ निजात मिलेगी।

— डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र

उत्तर प्रदेश आगरा के राजपुर गांव में स्थित खसरा नंबर 253 एवं 254 में कभी जल की अपार राशि रहा करती थी तथा वह जल आसपास के लोगों तथा जीव-जंतुओं के लिए जीवन अमृत प्रदान करता था, किंतु नवधनाढ्यों की नजर उस पर ऐसी लगी कि आज उस तालाब के स्थान पर विशाल अट्टालिकाएं खड़ी हैं। कानपुर आगरा राजमार्ग पर एत्मादपुर से पहले कभी एक विशाल तालाब 'बुढ़िया का तालाब' विशाल दरिया के रूप में स्थित था, जिसमें रजवाहे के माध्यम से पानी निरंतर आता रहता था और वह वर्ष पर्यंत लबालब पानी से भरा रहता था। किंतु अब वहां पर पानी का नामोनिशान नहीं है तथा बबूल सहित कांटेदार वृक्षों का जंगल खड़ा हो गया है। प्रयागराज स्थित तालाब नवल राय अब इतिहास का विषय बन गया है। शायद ही किसी को मालूम हो कि कभी यहां विशाल तालाब था जिसके स्थान पर आज इस नाम का मोहल्ला कायम हो गया है। प्रयागराज में ही बारा तहसील के लालापुर मार्ग पर स्थित धरा गांव का तालाब अपने आप में अद्वितीय था, 40 एकड़ में फैले इस तालाब की भूमि कंक्रीट की बनाई गई थी और उसमें चारों ओर से आकर बरसाती पानी जमा होता था तथा वह अड़ोस पड़ोस के गांवों सहित धरा गांव के लोगों तथा अन्य जीव-जंतुओं के पेयजल के साथ-साथ फसलों की सिंचाई एवं अन्य आवश्यक कार्यों में उपयोग में लाने पर भी वर्ष पर्यंत लबालब भरा रहता था किंतु आज वहां पानी के स्थान पर सूखी भूमि नजर आती है। गोरखपुर स्थित असुरन पोखरा जिसे सन 1075 से 1077 के मध्य राजा शूरपाल ने विष्णु मंदिर के साथ बनवाया था। आज पानी रहित होकर असुरन मोहल्ले के नाम से गोरखपुर में जाना जाता है। कानपुर देहात घाटमपुर स्थित कुष्मांडा देवी मंदिर का तालाब भी अपनी यही कहानी कह रहा है। गाजीपुर के सिद्ध पीठ भुड़कुड़ा के उत्तरी छोर पर स्थित पोखरा चमत्कारी पोखरा के नाम से जाना जाता है जिसे सिद्ध पीठ के दूसरे महान संत गुलाल साहिब ने संवत् 1766 में लगभग 550 वर्ष पहले खुदवाया था,



आज अपने अस्तित्व से जूझ रहा है तथा अंतिम सांसे ले रहा है। इसी प्रकार अलीगढ़ से अतरौली स्थित राजमार्ग पुर गांव का तालाब, शाहजहांपुर की तहसील तिलहर और पुवाया की सीमा में लघौला चेना में 84 बीघा के विशाल क्षेत्र में फैला तालाब, अमेठी के 109 हेक्टेयर में फैला हुआ समदा ताल, नोएडा के बिलासपुर में स्थित 40 बीघा में फैले बूढ़े बाबा का तालाब, मुरादाबाद के खुशहालपुर रोड में स्थित लोको शेड के पास स्थित तालाब तथा चित्रकूट जिला कलेक्ट्रेट के पास स्थित चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए मिनी खजुराहो के नाम से विख्यात गणेश बाग स्थित बावड़ी एवं तालाब आज अपने अस्तित्व को गंवाकर अंतिम सांसे ले रहे हैं, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। कभी समीपवर्ती गांव के सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजनों के केंद्र बनने वाले यह तालाब आज मृतप्राय हो गये हैं तथा अपने जीवन की रक्षा के लिए किसी भगीरथ की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

जीवन में जल का महत्व सर्वोपरि है, उसके बिना जीवन की कल्पना कर पाना ही असंभव है। भारतीय मिथकों में ईश्वर का प्रथम अवतार जल में 'मत्स्य अवतार' के रूप में ही हुआ है, जो यह प्रतिपादित करता है कि जीवन का मूल स्रोत जल ही है, जिसके दृष्टिगत भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का विकास प्रायः जल स्रोत नदियों के तट पर ही हुआ है। मानव ने जल के महत्व को समझा और प्राणी मात्र के लिये जल की उपलब्धता सुनिश्चित बनाए रखने के लिए प्राकृतिक संसाधनों के अतिरिक्त कुंआ, बावड़ी, पोखर और तालाब अनेकानेक जल स्रोतों का निर्माण कर उन्हें प्राणी मात्र के लिए उपलब्ध कराया। पानी के यह स्रोत न केवल मानव जीवन के लिए उपयोगी थे अपितु वनों में विचरण करने वाले वन्य प्राणियों के साथ ही साथ वन संपदा के संवर्धन



आज पूरे देश में पोखर और तालाबों के समक्ष अस्तित्व का संकट खड़ा हुआ है, अनेकानेक तालाब सूख कर सिमट गए हैं तथा अंतिम सांसे ले रहे हैं। बहुतों ने तो अपना अस्तित्व ही गंवा दिया है।

तथा फसलों की समृद्धि के लिए भी उतने ही उपयोगी थे।

सबको आवश्यकतानुसार पर्याप्त जल समय-समय पर प्राप्त होता रहा है, जिससे प्रकृति के संपूर्ण अंग पूर्ण रूप से पुष्पित पल्लवित होते रहे हैं किंतु विकास की अंधी दौड़ में भू माफिया, राजनेता तथा अधिकारियों के गठजोड़ की दूषित नजर जब इन जल स्रोतों पोखर तालाबों पर पड़ी तो उन्हें इनमें अपार धन राशि की संभावना दिखाई दी जिसके लिए वह एक सूत्र में बंध कर इन जल स्रोतों को हड़पकर उन पर कंक्रीट के जंगल उगाना प्रारंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप कभी पूरी भारत भूमि में कोस कोस में रहने वाले पोखर और तालाब लुप्तप्राय हो गए हैं। देश के बड़े-बड़े महत्वपूर्ण शहरों की पेयजल व्यवस्था इन्हीं तालाबों पर निर्भर थी, किंतु दिन प्रतिदिन समाप्त हो रहे पोखर और तालाबों के कारण पेयजल की समस्या भी गंभीर स्वरूप धारण कर उपस्थित हुई है।

आज पूरे देश में पोखर और तालाबों के समक्ष अस्तित्व का संकट खड़ा हुआ है, अनेकानेक तालाब सूख कर सिमट गए हैं तथा अंतिम सांसे ले रहे हैं। बहुतों ने तो अपना अस्तित्व ही गंवा दिया है।

आज देश का तीन चौथाई भाग पेयजल की समस्या से जूझता नजर

आता है। देश के अनेक भागों में जल की अनुपलब्धता के कारण आंदोलन और संघर्ष हो रहे हैं। दक्षिण भारत के चेन्नई से लेकर उत्तर भारत के अनेक शहरों में पेयजल की समस्या मुंह बाए खड़ी है। देश के लगभग 70 प्रतिशत घरों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है। लोग प्रदूषित पानी पीने के लिए बाध्य हैं, जिसके चलते लगभग 4 करोड़ लोग प्रतिवर्ष प्रदूषित पानी पीने से बीमार होते हैं तथा लगभग 6 करोड़ लोग प्लोराइड युक्त पानी पीने के लिए विवश हैं। उन्हें पीने के लिए शुद्ध जल उपलब्ध नहीं है। देश में प्रतिवर्ष लगभग 4000 अरब घन मीटर पानी वर्षा के जल के रूप में प्राप्त होता है किंतु उसका लगभग 8 प्रतिशत पानी ही हम संरक्षित कर पाते हैं, शेष पानी नदियों, नालों के माध्यम से बहकर समुद्र में चला जाता है। हमारी सांस्कृतिक परंपरा में वर्षा के जल को संरक्षित करने पर विशेष ध्यान दिया गया था, जिसके चलते स्थान स्थान पर पोखर, तालाब, बावड़ी, कुआं आदि निर्मित कराए जाते थे, जिनमें वर्षा का जल एकत्र होता था तथा वह वर्ष भर जीव-जंतुओं सहित मनुष्यों के लिए भी उपलब्ध होता था, किंतु वैज्ञानिक प्रगति के नाम पर इन्हें संरक्षण न दिए जाने के कारण अब तक लगभग 4500 नदियां तथा 20000 झील, पोखर, तालाब आदि सूख गये हैं तथा वह भू

माफिया के अवैध कब्जे का शिकार होकर अपना अस्तित्व गवा बैठे हैं।

देश का कोई भी ऐसा हिस्सा या प्रदेश नहीं है जहां पर पोखर एवं तालाब दिन प्रतिदिन सूख न रहे हों तथा उन पर भू माफिया तथा बिल्डरों का अवैधानिक कब्जा न हुआ हो। इसे देखते हुए प्रकृति प्रेमी तथा जल संरक्षण तथा संवर्धन की दिशा में कार्य कर रहे लोगों द्वारा समय-समय पर ऐसे जल स्रोतों की सुरक्षा हेतु माननीय उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में भी गुहार लगाई गई। श्री हिंचलाल तिवारी, जगपाल व अन्य की जनहित याचिका में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा देश के सारे झील तालाब झरनों को अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश दिया गया था इसके बाद गाजीपुर के इकबाल अहमद की जनहित याचिका में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के तत्कालीन न्यायमूर्ति श्री शंभू नाथ श्रीवास्तव ने सुनवाई करते हुए तालाबों से अतिक्रमण हटाने के लिए 2005-06 में आदेश पारित करते हुए कहा गया कि 1952 के पहले के राजस्व अभिलेखों में पोखर, तालाब आदि के रूप में अंकित जलाशयों को अतिक्रमण मुक्त कर उन्हें बहाल किया जाए।

माननीय न्यायालयों द्वारा पारित उक्त निर्णयों श्री समस्या विशेष का तो समाधान हुआ तथा कुछ जलाशयों को जीवनदान मिला किंतु उनका उनका व्यापक प्रभाव नहीं पड़ा, भू माफिया राजनेता एवं अधिकारियों के गठजोड़ ने जलाशयों की मुक्ति एवं उनकी बहाली की दिशा में ठोस कार्यवाही नहीं की गई। उत्तर प्रदेश के आगरा के राजपुर गांव के खसरा नंबर 253 एवं 254 में स्थित तालाब को बहाल कराने हेतु संघर्ष कर रही सपोर्ट इंडिया वेलफेयर सोसाइटी आगरा के लोग उक्त निर्णय के आलोक में शासन प्रशासन से संबंधित तालाब की मुक्ति

हेतु निरंतर अनुनय विनय करते रहे किंतु परिणाम कुछ नहीं निकला। हार कर उन्होंने भी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की शरण ली और जनहित याचिका दाखिल कर तालाब को मुक्त कराने का अनुरोध किया जिसमें निर्णय पारित करते हुए जिलाधिकारी आगरा को संबंधित तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराकर उसे बहाल कराने का आदेश दिया गया किंतु जिलाधिकारी उसे अतिक्रमण मुक्त कराकर बहाल नहीं करा सके क्योंकि संबंधित तालाब में कंक्रीट की अट्टालिकाओं का मायाजाल फैला हुआ था।

भू-माफिया राजनेता एवं अधिकारियों का रचना संसार अपने प्रभाव से जिलाधिकारी को तालाब को अतिक्रमण अतिक्रमण मुक्त कराने में सफल नहीं होने दिया। फलस्वरूप जनहित याचिकाकर्ता 'सपोर्ट इंडिया वेलफेयर सोसाइटी' ने पुनः एक बार माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की शरण जनहित याचिका संख्या 1479/19 के माध्यम से ली, जिसमें निर्णय पारित करते हुए न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार सिंह बघेल तथा न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल की खंडपीठ ने प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को तालाबों से अतिक्रमण हटाकर उनकी पुनर्बहाली का आदेश दिया है आदेश में कहा गया है कि प्रदेश में 1951-52 के राजस्व अभिलेखों में अंकित तालाबों अतिक्रमण हटाकर उन पर किए गए पट्टे समाप्त करके उनकी बहाली का निर्देश दिया है साथ ही मुख्य सचिव को राजस्व परिषद के चेयरमैन के परामर्श से एक मानिट्रिंग कमेटी गठित करने का निर्देश देते हुए कहा है कि प्रदेश के प्रत्येक जिला अधिकारी अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व तालाबों की सूची तैयार करें तथा अतिक्रमण हटा कर उनकी पुनर्बहाली का कार्य करें। साथ ही कार्रवाई की सूचना मुख्य सचिव द्वारा

गठित मानिट्रिंग कमेटी को हर छह माह में सौंपी जाए, कमेटी को भी तीन या चार माह में अवश्य बैठक करके तथा तालाबों की बहाली की रिपोर्ट पर विचार करने का आदेश दिया गया है। न्यायालय ने जिलाधिकारी आगरा को तालाब को बहाल कर अपनी रिपोर्ट 3 माह के भीतर महानिबंधक माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पेश करने का आदेश दिया है। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि मानिट्रिंग कमेटी में पूर्व न्यायाधीश श्री राम सूरत राम मौर्या को भी आमंत्रित किया जाए। पहले से गठित राज्य स्तरीय जिला स्तरीय समितियां भी अपनी रिपोर्ट नवगठित कमेटी को दें, राज्य के अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के आदेशों के पालन में लापरवाही बरती है अब अगर लापरवाही बरती जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

निश्चित रूप से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश से प्रदेश की नौकरशाही पर सही कार्य करने का दबाव बनेगा तथा वह अन्य समस्त दबावों से अपने आप को अलग रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में समस्त कार्यवाही करते हुए विलुप्त हो गए या विलुप्त हो रहे पोखरों तालाबों से अतिक्रमण हटाकर उन्हें पुनर्जीवित करने का कार्य करेंगे। जिससे विलुप्त हो रही हमारी संस्कृति तथा जीवन के मूलाधार पोखर एवं तालाब पुनर्जीवित होंगे। पोखर और बावड़ी अपने आगोश में बरसाती जल को समेट कर जहां एक और प्रकृति तथा जीव जंतुओं को वर्ष पर्यंत अपने जल से संतुष्टि प्रदान करेंगे, वहीं दूसरी ओर वर्षा के जल को बहने से रोककर भूगर्भ के जल को भी संरक्षण तथा संवर्धन प्रदान करने का कार्य करेंगे जिससे भूगर्भ जल का स्तर भी ऊपर उठेगा तथा पानी की समस्या से कुछ निजात मिलेगी। □□

प्लास्टिक कचरे से खतरा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकल उपयोग (सिंगल यूज) प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर मानवता को बचाने का सफल प्रयास किया है। कई एक सत्य तथ्य हैं कि प्लास्टिक जीवन के लिए खतरा बन गया है। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार 2014 में विश्व में प्लास्टिक उत्पादन 311 मीट्रिक टन था, जो कि 2050 तक 1124 मीट्रिक टन हो जाने की संभावना है। यह एक भयावह आंकड़ा है। इस मात्रा में अगर प्लास्टिक कचरा पृथ्वी पर होगा तो पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव-जंतुओं के लिए मौत का सामान ही होगा।

अध्ययन के मुताबिक 2050 तक समुद्र में मछली की तुलना में अधिक प्लास्टिक होगा। 2014 तक समुद्र में मछली और प्लास्टिक का वजन अनुपात 1:5 का था, जोकि 2050 में यह 1:1 यानि बराबर-बराबर का खतरनाक स्तर का होगा। इसी के अनुपात में कार्बन बजट में भी प्लास्टिक के शेयर 1 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक होने के अनुमान हैं।

दिल्ली में हर दिन 9,000 टन से अधिक कचरा उत्पन्न होता है, जिसके तीन चौथाई हिस्से को प्रतिबंधित प्लास्टिक की थैलियों में लपेटा जाता है। इससे हर दिन लगभग 600 टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है। पूरे भारत में प्रतिदिन 15,000 टन प्लास्टिक का उपयोग होता है, जिसमें से 43 प्रतिशत एकल उपयोग प्लास्टिक है। एकल उपयोग प्लास्टिक एक भयावह खतरा है। प्लास्टिक ने कई उद्योगों में जूट, एल्युमिनियम, स्टील और प्राकृतिक रेशों का स्थान ले लिया है। लेकिन यह पुनर्चक्रण के लिए स्थापित अपशिष्ट संग्रह प्रणाली से परे है। यह सदियों से पृथ्वी और महासागर की सतह पर तैरता रहा है और हमारे समुद्री जीवन, मत्स्य पालन, खेती आदि को नुकसान पहुंचाता रहा है।

ऐसे में इस भयावह प्लास्टिक से निजात पाने के लिए प्रधानमंत्री के आह्वान पर सभी हितधारकों, उपभोक्ताओं, उत्पादकों और नियामकों को इसके भयावह तमाशा से निपटने के



प्लास्टिक कचरे की भयावहता को देखते हुए प्रधानमंत्री का यह कदम निश्चित रूप से देश ही नहीं दुनिया के लिए एक सकारात्मक पहल है।

प्रधानमंत्री की छवि वर्तमान में दुनिया के देशों के बीच मानवता के लिए ठोस कदम उठाने वाले नेता के रूप में उभरी है।

— के.के. श्रीवास्तव



लिए योगदान देना होगा। काश, हम इसके प्रति सचेत होते। प्रधानमंत्री की सदिच्छा से सुर मिलाते हुए इरादे और कार्रवाई दोनों पर खरे उतरते। आतंकवाद की तरह मानव मन, पर्यावरणीय क्षति के बारे में सचेत और तत्काल कार्यवाही के बारे में क्यों नहीं सोचता? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम केवल जीवित प्राणियों और उनके बुरे डिजाइनों के बारे में सोचते रहते हैं। अगर ग्लोबल वार्मिंग को लेकर हम पर कोई बड़ी त्रासदी आई होती, तो हम अधिक चिंतित होते। दूसरा, कि हम इससे अज्ञानतावश दूरी बनाये हुए है क्योंकि हमारे दिमाग में यह बात जमी हुई है कि इससे कोई बड़ा नुकसान फिलहाल नहीं है। क्योंकि वातावरण में फैले रसायन के बारे में मानव समाज में कोई नैतिक नियम नहीं हैं। तीसरा, भविष्य का खतरा अभी स्पष्ट नहीं है। हम एक स्पष्ट और एक समकालीन हमले के बारे में चिंतित इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसे खतरों के प्रति हमारी दृष्टि नहीं पहुंची है।

प्रतिबंधित प्लास्टिक को लेकर कुछ भ्रामक बातें भी हितधारकों द्वारा फैलाई जाती रही है जैसे कि अगर एकल उपयोग वाला प्लास्टिक किसी रसायन से धो दिया जाए तो उसके विषाणु समाप्त हो जाते हैं। इससे फिर कोई खतरे की आशंका नहीं रहती। पर उपभोक्ताओं को परिवर्तित करने के लिए हमें एक विपणन दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। 'सक्रिय' ग्राहक के साथ जुड़ाव की आवश्यकता है और इसके लिए यह जानना आवश्यक है कि प्लास्टिक के पर्यावरण के अनुकूल विकल्प के रूप में वह क्या चाहता है?

प्लास्टिक के स्थान पर विकल्प के रूप में ऐसी कौन सी चीज सामने लाई जाए जो मूल्य, गुणवत्ता तथा बदलते जलवायु के अनुसार हित में हो? किस प्रकार की अंतर्निहित अपील



वर्ष 2000 में प्लास्टिक के उत्पादन में बढ़ोतरी के कारण एकल उपयोग वाली प्लास्टिक पैकेजिंग और इसके परिणामस्वरूप गलत तरीके से इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक कचरे का एक विशालकाय ढेर बन गया

(कार्यात्मक, भावनात्मक या सामाजिक) के साथ समाज को इसके प्रति अग्रसर किया जा सकता है? इन सवाले के उत्तर के क्रम में बाजार की संरचना, सामग्री के उपयोग और स्काउटिंग सेवाओं में नवाचार के माध्यम से बाजार में पर्यावरणीय सुधार की आवश्यकता है। ग्राहकों की अंतरंगता और प्रतिस्पर्धी लाभ को नए रणनीतिक ढांचे से देखने की जरूरत है। एक वाजिब मूल्य श्रृंखला के साथ सहयोग को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है ताकि उनके बदले हुए खरीदारी पैटर्न पर जलवायु के प्रभाव को शामिल किया जा सके।

प्लास्टिक का उत्पादन और उपयोग करने के तरीके को बदलने में

उत्पादकों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। वर्ष 2000 में प्लास्टिक के उत्पादन में बढ़ोतरी के कारण एकल उपयोग वाली प्लास्टिक पैकेजिंग और इसके परिणामस्वरूप गलत तरीके से इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक कचरे का एक विशालकाय ढेर बन गया है। वर्तमान में दुनिया में हर साल 300 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है, जिसका प्रबंधन करने के लिए क्षमता, बुनियादी ढांचे, या सामूहिक शक्ति की आवश्यकता होती है। सालाना 8 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा समुद्र में बह जाता है, जबकि भूमि पर बचे हुए कचरे के कमजोर और कुप्रबंधन से सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट पैदा हो जाता है। मैकिन्से, एलेन मैकआर्थर और डब्ल्यूईएफ की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार प्लास्टिक उपयोग के कारण वास्तव में 40 अरब डॉलर मूल्य का नकारात्मक खर्च होता है, जो कि निर्माताओं के वास्तविक मुनाफे से अधिक हैं। हालांकि भारत अभी बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक नहीं है, लेकिन इसकी वर्तमान खपत के स्तर को देखते हुए, आने वाले दिनों में इसके बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि भारत में उत्पन्न कुल कचरे में से कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरा अमेरिका की तुलना में लगभग 2 प्रतिशत है। यह 2 प्रतिशत

का आंकड़ा हर रोज तकरीबन 33.1 मिलियन पाउंड का होता है। जिसमें से केवल 19.8 मिलियन मूल्य के कचरे को एकत्र कर उसका पुनर्नवीनीकरण किया जाता है। इस तथ्य से चिंतित एचयूएल, आईटीसी, कोका कोला और भारत में अन्य कंपनियों ने हाल ही में 2025 तक 100 प्रतिशत पुनर्नवीनीकरण पैकेजिंग को अपनाने और आगे चलकर एकल उपयोग प्लास्टिक पैकेजिंग को खत्म करने का संकल्प लिया है। स्थानीय स्तर पर, सामाजिक उद्यमी ठोस परिवर्तन प्रदान कर रहे हैं, प्लास्टिक कचरे को पुनः उपयोग योग्य सामग्री बनाने और अन्य उत्पादों में परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे हैं।

हमें प्लास्टिक को बनाने, उपभोग करने, पुनर्नवीनीकरण और पुनः उपयोग करने के तरीके में क्रांति लाने की आवश्यकता है। फिलहाल हमें यह मान लेना चाहिए कि एकल उपयोग प्लास्टिक, विशेष रूप से प्लास्टिक बैग को, तुरंत प्रतिस्थापित करना लगभग असंभव है। क्योंकि कपास की थैलियों जैसे विकल्प अपने कार्बन फुटप्रिंट को देखते हुए पर्यावरण के अनुकूल नहीं हो सकते हैं। प्लास्टिक के सभी विकल्प प्लास्टिक की तुलना में या तो अधिक महंगे हैं या कम आसानी से उपलब्ध हैं। इस प्रकार हमें पहले कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के मुद्दे पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, प्लास्टिक पैकेजिंग में वैश्विक प्लास्टिक उत्पादन का 40 प्रतिशत शामिल है। हमें प्लास्टिक उत्पादन, उपभोग, निपटान और पुनः प्राप्ति के लिए एक परिपत्र अर्थव्यवस्था मॉडल में परिवर्तन करके एक नई प्लास्टिक अर्थव्यवस्था बनाने की आवश्यकता है। इसमें आरंभिक



हमें प्लास्टिक को बनाने, उपभोग करने, पुनर्नवीनीकरण और पुनः उपयोग करने के तरीके में क्रांति लाने की आवश्यकता है।

उपयोग के साथ प्लास्टिक उत्पादों को पुनः उपयोग, पुनर्नवीनीकरण और खाद बनाने के लिए उपभोक्ताओं की स्थिरता और सशक्तिकरण के साथ डिजाइन की गई अभिनव पैकेजिंग सामग्रियों को अपनाना शामिल होगा। इन सभी अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं के लिए अपशिष्ट समस्या को दूर करने के लिए कई गुना विकास करना होगा। मैकिन्से के अनुसार, यह प्लास्टिक क्षेत्र की नकारात्मकता को काफी कम कर देगा। वर्तमान में पॉलीथीन के लिए पुनर्नवीनीकरण की दर केवल 10 प्रतिशत है। 80 प्रतिशत स्टील और 75 प्रतिशत एल्यूमीनियम के डिब्बे की तुलना में, प्लास्टिक 40 प्रतिशत से कम की दर से पुनर्नवीनीकरण करता है।

प्लास्टिक कचरे की भयावहता को देखते हुए प्रधानमंत्री का यह कदम निश्चित रूप से देश ही नहीं दुनिया के लिए एक सकारात्मक पहल है। प्रधानमंत्री की छवि वर्तमान में दुनिया के देशों के बीच मानवता के लिए ठोस कदम उठाने वाले नेता के रूप में उभरी है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर योग को महत्व

दिलाने के बाद दुनिया भर के लोगों को प्लास्टिक के कचरे से मुक्ति दिलाने का जो बीड़ा नरेंद्र मोदी ने उठाया, अब दुनिया के अन्य देश भी इस नक्शे पर चलने के लिए रणनीतिक तैयारियों के साथ आगे आये हैं। प्रधानमंत्री के आह्वान को देश के नागरिकों ने गंभीरता से लिया है। भारत के सभी शहरों, राज्यों, यहां तक कि छोटे-छोटे कस्बों और मौहल्लों में भी राज्य प्रायोजित जागरूकता का सिलसिला चल रहा है। मार्च 2018 में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2016 में संशोधन किया गया। संशोधन का उद्देश्य है कि वर्ष 2020 तक एकल उपयोग प्लास्टिक के कचरे से देश के

लोगों को मुक्ति दिलाना। लेकिन इस राह में अभी रोड़े भी हैं। प्लास्टिक उद्योग में लगे 40 लाख श्रमिकों के बारे में अभी कोई स्पष्ट दिशा नहीं दिखती। वहीं उपभोक्ता एकल उपयोग प्लास्टिक के स्थान पर किस चीज का प्रयोग करेंगे इसकी तस्वीर भी अभी साफ नहीं है। क्योंकि जो कुछ विकल्प मौजूद हैं उससे भी पर्यावरण को हानि पहुंचने की प्रबल संभावना है। दूसरी तरफ प्लास्टिक की थैलियों, कपों, प्लेटों, छोटी बोतलों, छोटे-छोटे पाउचों सहित कई तरह के जनता के दिनचर्या में शामिल हो चुके लगभग आवश्यक उत्पादों पर भी प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्लास्टिक कचरे की वृद्धि में इनका भी योगदान बढ़ा है।

कुल मिलाकर प्रधानमंत्री की इस पहल में अभी अगर-मगर भी बहुत हैं। लेकिन कहा जाता है कि एक अच्छी दृष्टि से शुरू किया गया काम अंशशोधित तथा क्रमिक दृष्टिकोण के चलते हर तरह की हिचकिचाहट को दूर कर देता है। इस मामले में भी इसी ही आशा की जानी चाहिए। □□

लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं।

क्यों नहीं हो पाया भारत अमरीकी व्यापार समझौता?

भारत-अमरीकी के बीच मधुर राजनयिक संबंधों के बावजूद अमरीकी प्रशासन के कड़े और अनुचित रुख के चलते दोनों देशों के बीच प्रस्तावित तथा बहुप्रतीक्षित सीमित व्यापार समझौता नहीं हो सका। भारत की ओर से इस समझौते के लिए उपयुक्त माहौल बनाने की भरसक कोशिश हुई लेकिन ट्रंप प्रशासन द्वारा भारतीय हितों की अनदेखी के चलते इसे मुकाम तक नहीं पहुंचाया जा सका।

मालूम हो कि सितंबर के अंतिम सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमरीकी यात्रा खासी सुर्खियों में रही। हॉस्टन में हाऊडी-मोदी रैली हो या संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी का भाषण, सभी की चर्चा देश-दुनिया में हुई। पहली बार भारत अमरीकी संबंधों में बराबरी की झलक दिखाई दी, जब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने एकसाथ मंच साझा किया और अमरीका में बसे भारतीयों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर, अमरीका में अपनी संख्यात्मक शक्ति का अहसास करवाया। ऐसे में एक समाचार जो सभी को हैरान करने वाला था कि इस दौरान भारत अमरीकी व्यापार समझौता नहीं हो पाया। वास्तव में यह कोई विस्तृत व्यापार समझौता नहीं होकर एक सीमित समझौता ही था, उसके बावजूद भारत और अमरीका में कोई सहमति नहीं बन पाना अटपटा लगा।

कहा जा रहा है कि अमरीका के सख्त एवं अड़ियल रवैये के कारण यह समझौता नहीं हो पाया। हालांकि भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल इस समझौते हेतु अमरीका में मौजूद थे, लेकिन आम सहमति नहीं बन पाने कारण उन्हें खाली हाथ ही स्वदेश लौटना पड़ा।

क्या है विवादास्पद मुद्दा

सर्वविदित है कि पिछले कुछ समय से अमरीका ने चीन और भारत से व्यापार युद्ध छेड़ रखा है। विश्व व्यापार समझौते (डब्ल्यूटीओ) के बावजूद अमरीका चीन के साथ-साथ भारत से आने वाले उत्पादों पर भी आयात शुल्क बढ़ाता जा रहा है। यहीं नहीं दशकों से भारत से आने वाले कई उत्पादों को प्राथमिकता देते हुए जो शुल्क में रियायत दी जा रही थी, उसे भी समाप्त कर दिया गया। उसके खिलाफ भारत जो अभी तक अमरीका के आक्रामक

अमरीका को समझना होगा कि भारत यदि अपने छोटे व्यापारियों के हित में, ई-कामर्स कंपनियों के डिस्काउंट पर रोक चाहता है, या चिकित्सा में काम आने वाली दवाओं या इंप्लांट की कीमतों पर नियंत्रण करता है या अपने उद्योगों को संरक्षण के लिए आयात शुल्क बढ़ाता है तो यह गलत नहीं है।
— स्वदेशी संवाद



रुख को अनदेखा कर रहा था, उसने भी अमरीका से आ रहे उत्पादों पर शुल्क बढ़ाकर जवाबी कार्यवाही करते हुए अमरीकी रुख का प्रतिकार किया।

हालांकि हाल फिलहाल में तो यह मुद्दा नहीं उठा, लेकिन यह सभी जानते हैं कि अमरीकी कंपनियां और सरकार हमेशा से भारतीय पेटेंट कानून में जन स्वास्थ्य की रक्षा हेतु कई प्रावधानों और किसान की सुरक्षा हेतु बीज, पौधों और जीवन के पेटेंट की मनाही के खिलाफ शिकायत करती रही हैं। ६ यात्वय है कि मोनसेंटो नाम की कृषि कंपनी जीएम बीज के झूठे पेटेंट के नाम पर अभी तक किसानों से 8000 करोड़ रुपये की रायल्टी वसूल चुकी है। भारत में दवाईयों के पेटेंट का आधार पर कंपनियों पर प्रभावी अंकुश है।

वास्तव में अमरीकी ई-कामर्स कंपनियों द्वारा अनुचित रूप से दिये जा रहे डिस्काउंट और हिसंक कीमत नीतियों के चलते भारत सरकार द्वारा जो अंकुश लगाये गये हैं, उससे इन कंपनियों की शिकायत के कारण अमरीकी प्रशासन भारत पर दबाव बना रहा है कि इन कंपनियों को मनचाहे डिस्काउंट देने की अनुमति दे। लेकिन मुश्किल यह है कि इन डिस्काउंटों के कारण भारत के छोटे व्यापारी, रेहरी-पटरी के लोगों का धंधा चौपट हो रहा है और उनमें बेरोजगारी बढ़ रही है। वाणिज्य मंत्री द्वारा बार-बार यह कहा जा रहा है कि इन कंपनियों को डिस्काउंट देने की अनुमति देना संभव नहीं है। ये कंपनियां अपनी आर्थिक ताकत के आधार पर न केवल परंपरागत खुदरा व्यापार को नष्ट कर रही हैं, बल्कि नये ई-कामर्स स्टार्टअप भी इसके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं।

उधर कुछ समय पहले भारत सरकार द्वारा हृदय स्टेंट और घुटने इंप्लांट जैसे मेडिकल उपकरणों की कीमतों पर नियंत्रण लगाया गया था। इसका कारण यह था कि ये कंपनियां

मरीजों से मनमानी कीमत वसूल रही थी। कीमत नियंत्रण के कारण इन कंपनियों के अनुचित लाभों पर अंकुश लग गया है। अब ये कंपनियां अमरीकी प्रशासन के माध्यम से इन नियंत्रणों में ढील चाहती हैं।

अमरीकी प्रशासन यह भी चाहता है कि भारत अमरीका से दूध के आयात पर पाबंदी हटा दे। गौरतलब है कि अमरीका में दुग्ध उत्पादकों द्वारा गायों को रक्त एवं मांस का सेवन करवाया जाता है। चूंकि भारत में दूध एक शाकाहारी भोजन है, इस प्रकार से उत्पन्न दूध का आयात प्रतिबंधित है। लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत कर इस प्रकार के दूध का आयात किसी भी प्रकार से संभव नहीं है।

अमरीकी प्रशासन की यह शिकायत रहती है कि भारत द्वारा अत्यधिक दर पर आयात लगाये जाते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि भारत द्वारा औसत आयात शुल्क मात्र 10 प्रतिशत से भी कम है, जबकि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) द्वारा औसत 40 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने की अनुमति है।

अमरीकी प्रशासन का मानना है कि भारत को उसकी कृषि एवं दवा कंपनियों की मांग के अनुरूप अपने बौद्धिक संपदा कानून को बदलना चाहिए। अमरीकी मोटर साईकिल हार्ले डेविसन के आयात पर आयात शुल्क घटना चाहिए। हृदय स्टेंट और घुटनों के इंप्लांट पर कीमत नियंत्रण समाप्त करना चाहिए, ताकि अमरीकी कंपनियों के लाभ बरकरार रहें। अमरीकी दुग्ध उत्पादों को खुल तौर पर अनुमित हो, ई-कामर्स कंपनियों को डिस्काउंट देने की इजाजत हो और उन पर लगाये जा रहे अंकुश समाप्त हो जायें। आयात शुल्क, खास तौर पर टेलीकाम उत्पादों पर, हटाये जायें। यही मांगों को लेकर, अमरीका-भारत की व्यापार वार्तायें शुरू हुईं लेकिन कोई समझौता नहीं हो पाया।

संभव नहीं अधिकांश अमरीकी मांगों को मानना

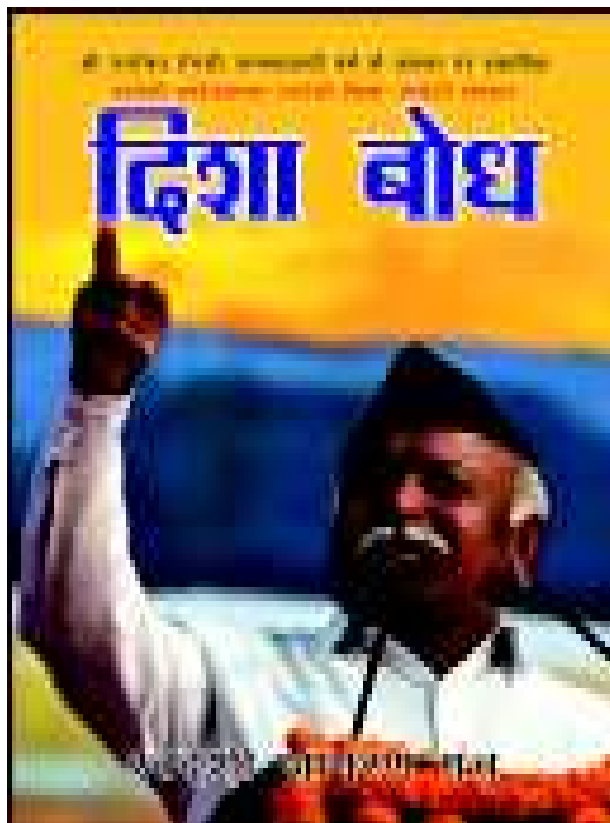
समझौते के लिए जरूरी है कि दोनों पक्षों की मांगों पर आपसी सहमति हो सके। लेकिन अधिकांश मामलों में अमरीकी रुख अकारण है। हार्ले डेविसन पर आयात शुल्क घटाना तो तब भी संभव हो सकता है, लेकिन जनस्वास्थ्य को ताक पर रखकर न तो हृदय स्टेंट और घुटनों के इंप्लांट पर कीमत नियंत्रण समाप्त करना संभव है और न ही पेटेंट कानूनों में अमरीकी इच्छानुसार बदलना। मांसाहारी पशुओं के दूध के आयातों पर भी पाबंदी हटाया जाना भारतीय मूल्यों और भावनाओं के अनुरूप संभव नहीं है।

आज जब हमारे आयात शुल्क पहले से ही काफी कम हैं, उन्हें और घटाना हमारे उद्योगों और कृषि के लिए घातक हो सकता है। जहां तक टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों पर आयात शुल्क घटाने का मामला है, उसमें भी कोई रियायत संभव नहीं है। अमरीका को समझना चाहिए कि यदि भारत यह मांग मान भी जाता है तो भी उसका लाभ चीन को ही मिलेगा।

कुल मिलाकर मधुर भारत अमरीकी राजनयिक संबंधों के बावजूद, अमरीकी प्रशासन के कड़े और अनुचित रुख के चलते भारत और अमरीका के बीच सीमिति व्यापार समझौता भी नहीं हो सका। अमरीका को समझना होगा कि भारत यदि अपने छोटे व्यापारियों के हित में, ई-कामर्स कंपनियों के डिस्काउंट पर रोक चाहता है, या चिकित्सा में काम आने वाली दवाओं या इंप्लांट की कीमतों पर नियंत्रण करता है या अपने उद्योगों को संरक्षण के लिए आयात शुल्क बढ़ाता है तो यह गलत नहीं है। अमरीका को भारत की चिंताओं को समझकर, इन मांगों को वापिस लेना चाहिए। □□

दिशा बोध

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत के द्वारा विजयदशमी के अवसर पर उद्बोधन के कुछ अंश...



हम बढ़ रहे हैं। लेकिन सारे विश्व में अर्थव्यवस्था चलती है। इसका एक चक्र होता है। समय-समय पर उसमें एक गतिरोध आता है। कहते हैं मंदी आई, अब मुझे एक सज्जन ने तो जिन्होंने बताया वह अर्थशास्त्र के जानकार हैं। उन्होंने बताया इसलिए आपको बता रहा हूँ — है या नहीं, पता नहीं। वे अर्थशास्त्र जानते हैं। उन्होंने कहा ये मंदी यानि रिसेशन तब कहा जाता है जब ग्रेथ रेट जीरो से नीचे चली जाए। फिलहाल हम तो पांच के आसपास हैं। हमको उसकी इतनी चिंता? चिंता तो करें — चर्चा क्यों करें? क्योंकि चर्चा से वातावरण बनता है, वातावरण में मनुष्य का आचरण होता है — तो अगर बहुत ज्यादा चर्चा करेंगे कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है तो और अर्थव्यवहार करने वाले लोग यह मानकर कि ऐसा हो रहा है — अपनी सुरक्षात्मक गतिविधियां शुरू करेंगे जो फिर से अर्थव्यवस्था की गति भी अवरुद्ध होगी। हम उपाय करने में जाएं। सरकार ने उपाय किए हैं, सरकार ने अपनी संवेदनशीलता का परिचय दिया है। उन्होंने कुछ उपाय किए हैं

लेकिन जैसा प्रमुख अतिथि महोदय ने कहा है अकेले सरकार यह नहीं कर सकती। हम सबको ध्यान में रखना होगा। हम सबको कुछ उपाय करने होंगे। कुछ सरकार को करने होंगे।

ये तो सरकार को झेलना ही पड़ता है न! अमरीका चीन की भी स्पर्धा चलती है, उसके परिणाम भी होते रहते हैं लेकिन हमको तो विश्वास रखना चाहिए, इतने सारे उपायों में से कुछ तो होगा ही, और मुख्य बात तो हमको यह देखना चाहिए कि सरकार कोई भी हो, किसी की भी हो, कुछ करें या ना करें, हमारे आर्थिक क्षेत्र में जो हस्तियां हैं वह बहुत मजबूत हैं। बड़ी हस्तियां, बड़े उद्योग जैसे आपके सामने यहां शिव नाडर जी बैठे हैं। एक भारतीय व्यक्ति सामान्य परिस्थिति से ऊपर आकर इतना बड़ा पराक्रम करता है और ऐसे एक नहीं हैं अपने जैसे कई उदाहरण हैं, और केवल अपने मुनाफे की चिंता करने वाले लोग नहीं हैं, वो सब लोग अपनी अधिक कमाई समाज के लिए खर्च हो, इसका ध्यान रखने वाले लोग हैं और अर्थव्यवहार की बहुत अच्छी समझ रखकर दुनिया के आर्थिक जगत में उन्होंने अपना एक स्थान बनाया है। ऐसे ही हमारे मध्यम और छोटे उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, अद्भुत गाथा है। यहां हमारे विभाग संघचालक जी उत्सव देखने आए हैं, पल्लवी स्वामी जी तिरुपुर से आते हैं, कभी तिरुपुर जाकर देखिए हमारा मध्यम उद्योग वाला, छोटे उद्योग वाला, क्या कर सकता है। वहां आदमी जाता है नौकर के नाते और मालिक बनता है। ये वहां की कीर्ति है। वहां के छोटे उद्योग, बड़े उद्योग, मध्यम उद्योग, वहां के आर्थिक संसाधन जो ऐसे उद्योगों के लिए पूंजी देते हैं, और काम करने वाले लोग, इनका एक समन्वय है। सब उसके आधार पर और वो सारा अपने देश का और दुनिया का एक महत्वपूर्ण निटवीयर हब बना है। ये चमत्कार हमारे लोग कर सकते हैं। हमको डरने की क्या आवश्यकता है? हम इस चक्र से बाहर आने वाले हैं। प्रयास की आवश्यकता है और प्रयास करते समय ध्यान में रखना पड़ेगा। सरकार भी प्रयास कर रही है, और पूंजी चाहिए तो एफ.डी.आई. का आमंत्रण भी कर रही है— कुछ उद्योग, उनका निजीकरण भी चल रहा है — जब आवश्यक हो तो करने में दिक्कत भी नहीं है। ये उपाय हैं, कभी ऐसे भी हो सकता है, कभी वैसे भी हो सकता है। परंतु इसका उपाय जो है हमें सशक्त बनना है। बाहर की एफ.डी.आई. भी बुलाएंगे हम, आएगी कब? जब वहां के लोगों को भरोसा है कि यहां हम माल बनाएंगे तो हमको उसका वापस मिलेगा कुछ। तो जो देश आर्थिक दृष्टि से

सशक्त है — सशक्त कैसे होता है? हमारे देश के आर्थिक सशक्ति के कुछ आधार स्तंभ हैं, बहुत पहले से हैं। देश दुनिया में आई मंदी तेजी का हमारे यहां असर होता नहीं है। उसका कारण वे लोग हैं, हमारे यहां सेल्फ एंप्लॉयड सेक्टर है, कोपरेटिव सेक्टर है, खुदरा व्यापारी हैं, लघु मध्यम उद्योग हैं, एमएसएमई जिसको कहते हैं, छोटा अपना उद्योग चलाने वाले स्वरोजगार वाले लोग हैं, कृषि है, पर्यटन है। इनकी बहुत शक्ति है, इनमें बहुत संभावनाएं हैं। इसको विकसित करना चाहिए। रोजगार बढ़ाने से लोगों के हाथ में पैसा आता है, पैसा आने से लोग खरीदते हैं, खरीदने से अर्थव्यवस्था की गति बढ़ती है। तो हम जो करेंगे, हमारे देश का रोजगार बढ़ाएं, हम बहुत अच्छी योजना बना रहे हैं, उसका नीचे तक अमल ठीक से हो।

हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत छिद्र थे, जिससे हमारी संपत्ति बह जाती थी। वे छिद्रों को बंद करने का काम भी अच्छा चला है। उसके लिए कड़ाई भी करनी पड़ती है — बहुत अच्छी तरह कड़ाई हो रही है। लेकिन कड़ाई की बात जहां तक है, जो लोग प्रमाणिक है, नियम मानने वाले लोग हैं वह उस कड़ाई के कारण बड़े छटपटाते हैं, लेकिन देश के लिए सहन करते हैं — करना भी चाहिए। लेकिन जिनको नियम—कानून की परवाह नहीं है, जिनको पाप ही पाप करना है, वो अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। कड़ाई योग्य जगह हो और अतिरिक्त कड़ाई का प्रमाणिक लोगों को कष्ट न हो, इसकी चिंता होनी चाहिए। ऐसे कुछ उपाय कर लिए तो विदेशों पर निर्भर रहने की बात अपनी कम होगी।

हम संघ के लोग तो स्वदेशी वाले लोग हैं। लोगों को ऐसा लगता है, स्वदेशी यानि दुनिया से संबंध बंद करो। ऐसा नहीं है बिल्कुल। सबसे अधिक तो स्वदेशी वाले जानते हैं कि आज का युग परस्पर निर्भरता का है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, दुनिया पास में आ गई है, बहुत अच्छे घनिष्ठ पहले से आर्थिक संबंध होने पड़ते हैं। लेकिन किसके होते हैं? जो स्वावलंबी है, उसके ज्यादा होते हैं। उससे संबंध रखने में बाकी देशों को रस रहता है और इसलिए स्वदेशी यानि क्या है? दत्तोपत जी कहते थे, यह देशभक्ति का रूप है, देनन्दिन जीवन में। विनोबा जी कहते थे, स्वदेशी यानि स्वावलंबन और अहिंसा।

जो मैं अपने घर में बना सकता हूँ वह मैं बाजार से नहीं लाऊंगा और बाजार से लाना है तो जिनका रोजगार चल रहा है, उनके रोजगार पर संकट लाकर मैं नहीं करूंगा। मेरे गांव में चीज बनती है तो मेरे गांव का रोजगार मारकर मैं दूसरे गांव से क्यों लाऊँ? मेरे देश में नहीं होता है तो उसके बिना मेरा जीवन चल सकता है क्या? तो बिना चलाऊंगा। नहीं चल सकता तो ठीक है दूसरे देश से लाऊंगा। उनकी शर्तें रहेंगी, वो मुझे माननी पड़ेगी। लेकिन मैं मजबूरी में नहीं मानूंगा — विचारपूर्वक मानूंगा।

अपनी शर्तों पर सब देशों से व्यापारिक संबंधों को बनाने का नाम है 'स्वदेशी'। अपनी शर्तों पर संबंध बनाने का आर्थिक बल

स्वयं का रखना। अगर आप ना करोगे तो हमारा नुकसान नहीं है — हम कर लेंगे, परम कंप्यूटर नहीं देते हो, हमने बना लिया। ऐसी धमक रखकर परस्पर निर्भरता जो चलती है वो फिर लाभ हानि के तत्व पर नहीं चलती है। वो दोस्ती के तत्व पर चलती है। संबंध रखने के लिए चलती है। भारत का विश्वास है सारी दुनिया में कि वे सच्चे लोग हैं, इनके साथ व्यापार करने में हम घाटे में नहीं रहेंगे। वो विश्वास काम करेगा— तो विश्वास बना रहे, इसलिए हम लोगों को आर्थिक स्वनिर्भरता देने की व्यवस्था की ओर ही बढ़ना पड़ेगा। मूल से विचार करना पड़ेगा।

अब हमारे यहां गीर गाय हैं। ब्राजील के लोग उसको लेकर गए, अपनी गायों को अच्छा करने के लिए। आज सुनते हैं कि वहीं से हमने और वो आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन के लिए सीमन मांगा है। क्या जरूरत है भई? हमारे यहां गीर गाय है। अच्छी है। 28 से 32 लीटर दूध देने वाली हमारे लोगों ने पाली है। गुजरात में जगह—जगह मिलती है। गुजरात में अब ब्राजील से वापिस गीर नस्ल के और बीज को बुलाने की क्या जरूरत है?

स्वदेशी यहां आती है। हमारे पास है। हम देंगे दुनिया को। दुनिया को आवश्यकता रहती है। वो देना हमारे लिए साधन बन जाएगा।

विदेशी लोग व्यापार करते हैं — अच्छा है। अच्छे रहेंगे तो ठीक ही है। सावधान तो रहना ही पड़ेगा न। एक देश है, मान लीजिए, वो देश क्या करता है? अपने देश में बाहर की किसी कंपनी को आने नहीं देता। और किसी को आना है तो आओ ठीक है एक शर्त है, आपके डायरेक्टर बोर्ड में एक डायरेक्टर हम बताएंगे, वो रहेगा। हमारे देश का आदमी रहेगा और आपके हर निर्णय में उसकी सम्मति आवश्यक रहेगी। सारी दुनिया की बड़ी कंपनियों को मान लीजिए, उन्होंने अपना एक—एक आदमी रख दिया और उसकी सम्मति के बिना नहीं चलेगा, तो ये कंपनी उनकी हो गई। तो वो कंपनियां क्या करती हैं, भारत जैसे देश की छोटी कंपनियों को खरीदती है। नाम वही रहते हैं, कंपनी अलग रहती है। शेयर्स किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के हैं। उस बहुराष्ट्रीय कंपनी का क्या है, वो चाइना के अंदर चलती है। ऐसा अप्रत्यक्ष साम्राज्य दूसरे देश में अपना उत्पन्न करने का काम चलता है। हमको सावधान रहना पड़ेगा न। इसलिए 'स्वदेशी' की आवश्यकता है और स्वदेशी की ओर बढ़ना है तो 'मूल से हमको विचार करना पड़ेगा'। प्रचलित जो अर्थतंत्र है वो अनेक प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकता जीडीपी जैसे उसके जो मानक बने हैं वो अधूरे हैं, दोषपूर्ण हैं, ये भी आज के सब अर्थतंत्र कहते हैं। हम अपने देश के अनुकूल, अपने देश को आगे बढ़ाने वाली, अपने देश का रोजगार बढ़ाने वाली, अपने देश का उत्पाद और उत्पादन बढ़ाने वाली, पर्यावरण को कम से कम और न हानि करने वाली और कम से कम ऊर्जा में काम चलाने वाली, लोगों में समृद्धि के साथ सद्नीति लाने वाली अर्थव्यवस्था, उसका विचार क्यों न करें? उसकी तरफ

हमको बढ़ना पड़ेगा।

आज जो हमको स्थिति मिली है उसमें ही चलना पड़ेगा। उसमें चलने के लिए तरह-तरह के मोड़ लेने पड़ेंगे। वो लेने भी चाहिए, परंतु ऐसे मोड़ लेते समय ध्यान में यह रखना चाहिए कि इन घुमावदार रास्तों से गुजरकर हमको पहुंचना कहां है? और कितना बल प्राप्त करना है? कि आगे चलकर हमको ऐसे घुमाव न लेने पड़े, इसकी चिंता हमको करनी पड़ेगी। और इसकी चिंता करनी है तो मन में स्व की स्पष्ट कल्पना चाहिए।

स्व की स्पष्ट कल्पना शिक्षा से मिलती है। शिक्षा के बारे में विस्तारपूर्वक हमारे प्रमुख अतिथि महोदय ने कहा है। एक अंग उन्होंने शिक्षा का बताया है – शिक्षा की गुणवत्ता का। चौथी में पढ़ने वाला दूसरी का पाठ पढ़ नहीं सकता। ये कोई गुणवत्ता नहीं हुई। अमेरिका के लोग हमारे बच्चों के गणित में कुशलता की कीर्ति गाते हैं और हमारे यहां पांचवीं में पढ़ने वाला बालक गणित कर नहीं सकता। ये स्थिति अच्छी नहीं है। उसको तो सुधारना ही पड़ेगा।

परंतु आखिर शिक्षा है किसलिए? शिक्षा केवल पेट भरने के लिए है क्या? पेट भरने के लिए शिक्षा देनी नहीं पड़ती। जीवन सिखा देता है – अनुभव सिखाता है। परंतु शिक्षा मनुष्य को दी जाती है। इसलिए दी जाती है कि वह अच्छा मनुष्य बनें। उसके मन में स्व पैदा हो। जिसके मन में स्वयं की प्रतिष्ठा नहीं है वो कैसे प्रतिष्ठित बनेगा? दुनिया उसको क्या प्रतिष्ठा देगी? स्वभाषा-स्वभूषा-स्वसंस्कृति-स्वदेश-स्वपरंपरा-स्वपूर्वज, इन सबका गौरव सिखाने वाली, उत्कृष्टता-एक्सीलेंस मन में भरने वाली हर बात में उत्कृष्ट प्रवीणता उत्पन्न करने वाली, और ऐसी उत्कृष्टता को निस्वार्थ बुद्धि से, आत्मीयता से, करुणा की भावना से, देश के लिए, समाज में जहां आवश्यक है, ऐसे लोगों के लिए अर्पण कर देने वाला संस्कार देने वाली शिक्षा हमको चाहिए। कर्तव्य बोध, सुसंगति, तर्कनिष्ठा, सत्यनिष्ठा, करुणा के साथ-साथ मन में भरने वाली शिक्षा चाहिए।

नई शिक्षा नीति आ गई है – अच्छा है। केवल ढांचागत परिवर्तन से काम नहीं चलता। ये सारी बातें देनी पड़ेगी-पाठ्यक्रम से लेकर तो शिक्षकों के प्रशिक्षण तक सर्वत्र विचार करके ये शिक्षा का कंटेंट हमको करना पड़ेगा। वो काम होगा ऐसी आशा करते हैं। केवल सरकार के हाथों में शिक्षा नहीं है, निजी हाथों में भी है। वहां भी ये काम हो जाए।

और दूसरा शिक्षा का स्थान है अपना कुटुंब। वहां बहुत चिंताजनक स्थिति है। संस्कारों का क्षरण। मातृवत परदारेषु ऐसा कहने वाला हमारा देश है। सीता जी के अलंकार पहचानने को लक्ष्मण जी को कहा गया तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं केवल पैर की पंजनियां, उसी को पहचानता हूं, क्योंकि मैंने गर्दन उठाकर सीता भाभी का मुख कभी देखा नहीं। ऐसी परंपरा बताने वाले देश में हमारी मातृशक्ति न घर में सुरक्षित है न बाहर सुरक्षित है। ये स्थिति क्या हम सबको शर्म आए, ऐसी स्थिति नहीं लगती –

लज्जाजनक नहीं है। ये कैसे हो सकता है – हम इतने सारे लोग रहते हैं और मोहल्लों में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। हमको तो इसके बारे में समर्थ होना ही पड़ेगा। संरक्षण देना ही पड़ेगा। लेकिन हमारी मातृशक्ति को भी हमको सशक्त बनाना पड़ेगा, प्रबुद्ध बनाना पड़ेगा। बराबरी के साथ परिवार और देश का गाड़ा चलाने वाला अधिकार उसको देना पड़ेगा। वो कर लेंगी। उनको अवसर दीजिए। स्वतंत्रता दीजिए। उनको सहायता कीजिए। उनके राह को रोकिए मत। वो कर लेगी और कोई चिंता करने का कारण नहीं है। इससे परिवार का क्या होगा – क्योंकि वात्सल्य को हमारी माता बहने जितना जानती है उतना हम लोग नहीं जानते। भारतीय नारी की विशेषताएं हैं वत्सलता, और इसलिए उनकी उन्नति के मार्ग पर वो चल सके उतना बल उनके पैरों में भरना, वो चलने के लिए और कुछ सहायता मांगती है, वो सहायता देना – चलने के लिए रास्ता खुला रखना – उनको चलने की स्वतंत्रता देना, ये काम हमको करना पड़ेगा। अनेक काम संघ के स्वयंसेवक करते हैं। मातृशक्ति भी उनके साथ जुटी है। उस सारी मातृशक्ति ने मिलकर एक व्यापक सर्वेक्षण किया है जो दिल्ली में 24 सितंबर को प्रकाशित हुआ है। उस प्रकाशन के आधार पर अब आगे कुछ योजनाएं स्वयंसेवकों की कुछ चलेगीं। लेकिन केवल संघ का काम नहीं है ये हम सबका काम है। हम अपने घर से प्रारंभ कर सकते हैं। घर में ये वातावरण होना चाहिए संस्कार का। आखिर भ्रष्टाचार भी आता कहां से है? व्यसन मुक्ति की बात चलती है – व्यसन आते कहां से है? व्यसनो के मोह में अलिप्त रहने का संस्कार घर में नहीं मिलता। विवेक घर से नहीं मिलता। तो कच्ची आयु में सब बातों के शिकार हमारे घर के बच्चे हो रहे हैं। हमारे नौजवान हो रहे हैं।

चीन जैसे देशों को अफीम जैसे व्यसन में जकड़कर कितने ही वर्ष यूरोप के देशों ने चीन पर राज किया। इतनी लंबी और समृद्ध संस्कृति परंपरा वाला देश। व्यसनमुक्ति, ये प्रश्न है। उत्तर देना पड़ेगा। घर-घर में वातावरण से – घर में संस्कारों से, अपने उदाहरण से, अपने बच्चों के प्रति अपनी आत्मीय सजग दृष्टि रखने से, इसकी आवश्यकता है। भ्रष्टाचार भी ऐसे ही होता है न। मुझे मेरी जो योग्यता नहीं है वो धन मुझे चाहिए, वो लाभ मुझे चाहिए और उसके लिए जो परिश्रम करना है – मुझे शॉर्टकट चाहिए। मैं उतना लंबा जाना नहीं चाहता हूं। इसी को तो भ्रष्टाचार कहते हैं न। किसी भी हालत में ये पाने की बुद्धि कहां से आई? वहीं से आई घर से। हमारे उदाहरण से। हमारी अनदेखी के कारण। हमने अनजाने में अपनी परिवार के बच्चों का लक्ष्य बदल दिया। पैसा कमाने केवल लक्ष्य दिया। दान करने का लक्ष्य नहीं दिया। साथ में हमने उनको अधूरा रखा है और इसलिए अपने परिवारों में इन संस्कारों का प्रयास होना चाहिए। □

(भाषा का लिपिबद्ध लेखन- दीपक शर्मा (अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख, स्वदेशी जागरण मंच))

आरसीईपी पर मोदी सरकार ने पीछे लिए कदम?

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) समझौते पर प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया था कि भारत के सभी हितों को ध्यान में रखकर कोई फैसला लिया जाएगा। अंत में भारत ने आरसीईपी में शामिल न होने का फैसला लिया।

कहा जा रहा है कि आरसीईपी समझौते से पीछे हटने की वजह कई मसलों पर भारत को भरोसा नहीं मिल पाना, इनमें आयात में बढ़ोतरी से होने वाले अपर्याप्त संरक्षण, आरसीईपी सदस्य देशों के साथ 105 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा, बाजार पहुंच पर भरोसे की कमी, नॉन-टैरिफ प्रतिबंधों पर असहमति और नियमों के संभावित उल्लंघन शामिल हैं। चीन इसमें सबसे बड़ी वजह है।

11 अक्टूबर को जब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आरसीईपी पर बातचीत के सिलसिले में थाईलैंड जा रहे थे, तभी स्वदेशी जागरण मंच ने इस समझौते को लेकर अपनी आपत्ति जता दी थी और आंदोलन की चेतावनी दी थी। खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार को इस समझौते से ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए।

आपको बता दें कि स्वदेशी जागरण मंच ने साफ कर दिया था कि आरसीईपी के विरोध में संगठन विरोध प्रदर्शन करेगा और जिला अधिकारी के माध्यम से पीएम को ज्ञापन सौंपेगी, इसके बाद संगठन से जुड़े लोगों ने कई जिलों में अधिकारी से मिलकर ज्ञापन भी सौंपा था। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए स्वदेशी जागरण मंच ने तो 10 से 20 अक्टूबर तक इसके राष्ट्रव्यापी विरोध का ऐलान किया था। मंच का कहना है कि अभी तक भारत ने जितने मुक्त व्यापार समझौते किए हैं उनसे देश में सस्ते आयातित माल पट गए हैं और भारतीय मैन्युफैक्चरिंग को बड़ा नुकसान हुआ है। मंच ने सरकार से आग्रह किया कि वह आरसीईपी पर दस्तखत न करे। अगर ऐसा करते हैं तो इसके विरोध में सड़क पर उतरेंगे

स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक अश्विनी महाजन ने कहा था कि इस समझौते से भारत को नुकसान होगा, इसमें भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा चीन है।

गौरतलब है कि आरसीईपी ही एक मात्र मुद्दा नहीं है जिसका विरोध स्वदेशी जागरण मंच ने किया है, इसके पहले जब सरकार ने अपनी दूसरी पारी में देश को अगले 5 साल में 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा, तब वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य की घोषणा करते हुए कहा कि इसके लिए विकास योजनाओं पर कई लाख करोड़ रुपये खर्च

किए जाएंगे और सॉवरेन बॉन्ड के द्वारा विदेश से कर्ज लिया जाएगा। लेकिन स्वदेशी जागरण मंच ने विदेशी कर्ज लेने के मोदी सरकार के प्रस्ताव का विरोध करते हुए इसे राष्ट्रहित के खिलाफ बताया था।

<https://hindi.hnnews.in/news/kyu-virodh-ki-wajah-se-rcep-par-modi-sarkar-ne-piche-liye-kadam/76323>

जन्मशती पर भागवत ने दत्तोपंत ठेंगड़ी की सराहना की



राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस), स्वदेशी जागरण मंच व भारतीय किसान संघ (बीकेएस) के संस्थापक दत्तोपंत ठेंगड़ी को एक विनम्र व्यक्ति के रूप में याद किया। संघ प्रमुख ने कहा कि दिवंगत मजदूर नेता ने अपने सिद्धांतों से समझौता किए बगैर हमेशा दूसरों की परवाह की। भागवत ने ठेंगड़ी जी की जन्मशती पर एक साल तक चलने वाले उत्सव की शुरुआत करने वाले कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। उन्होंने कहा, 'दत्तोपंत एक विनम्र व्यक्ति थे जिन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता किए बगैर लोगों से संपर्क किया। उन्होंने जो उपदेश दिया उसका पालन किया और लोगों का विश्वास जीता'। संघ प्रमुख ने कहा कि ठेंगड़ी एक सजग व्यक्ति थे जिन्होंने लोगों को सही राह दिखाई और हमेशा उनका ध्यान रखा। वर्धा जिला निवासी हिंदू विचारक ठेंगड़ी संघ के प्रचारक थे।

<https://www.jagran.com/politics/national-bhagwat-praised-bms-founder-thengdi-on-birth-centenary-19744933.html>

आरसेप पर फैसले की उद्योग जगत और संगठनों ने की तारीफ

आरसेप पर भारत सरकार द्वारा लिए गए फैसले की उद्योग जगत और किसान संगठनों ने जमकर तारीफ की है। दुग्ध उत्पाद कंपनी अमूल ने सरकार के इस निर्णय को मील का पत्थर बताया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत ने आरसेप पर हस्ताक्षर नहीं करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इससे संबंधित भारत की

चिंताओं का संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर भारत ने इससे दूर रहने का फैसला किया है।

कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। सीआईआई के प्रेसिडेंट विक्रम किलरेस्कर ने कहा कि संगठन भारत सरकार के हर उस समझौते के साथ खड़ा है, जिसमें द्विपक्षीय हितों को ध्यान में रखा गया है। फिक्की के प्रेसिडेंट संदीप सोमानी ने भी आरसेप पर सरकार के पक्ष का समर्थन किया है। सोमानी ने कहा कि वे आरसेप के मुद्दे पर सरकार द्वारा लिए गए फैसले के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि इस डील में भारत की चिंताओं को ध्यान में नहीं रखा गया था, इसके अलावा बहुत से मुद्दे अनसुलझे थे। आरसेप पर चल रही बातचीत के दौरान ही कई सेक्टरों ने अपनी चिंताएं दर्ज कराई थीं। इनमें स्टील, प्लास्टिक, कॉपर, एल्यूमीनियम, मशीन टूल्स, पेपर जैसे उद्योगों ने इस पर अपनी चिंताएं जताई थीं।

डेयरी उद्योग ने भी इसको लेकर अपनी चिंताएं जताई थीं। इस उद्योग के साथ-साथ किसान संगठनों का कहना था कि 16 देशों के इस समझौते में देश के दुग्ध और डेयरी उद्योग को खतरा पैदा हो जाएगा। इस समझौते के बाद न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से बहुत अधिक मात्रा में डेयरी उत्पाद भारतीय बाजार में आ सकते थे। इससे कीमतों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता, जिसका अंतिम असर पहले से संकट से गुजर रहे किसानों पर दिखता।

<https://www.jagran.com/business/biz-industry-and-farmer-organizations-have-praised-the-governments-decision-on-rcep-19727516.html>

भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था की अगुवाई करेगा

भारत की अगुवाई में दक्षिण एशिया वैश्विक वृद्धि का केंद्र बनने की दिशा में बढ़ रहा है और 2040 तक वृद्धि में इसका अकेले एक-तिहाई योगदान हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) ने हालिया शोध में यह बात कही।

मुद्राकोष के भौगोलिक विभाजन में दक्षिण एशिया क्षेत्र में भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और मालदीव शामिल हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जगह नहीं दी गई है। आईएमएफ के एक दस्तावेज क्या वृद्धि के लिए दक्षिण एशिया तैयार है? सतत एवं समावेश वृद्धि एजेंडा में कहा गया कि बुनियादी ढांचे में सुधार और युवा कार्यबल का सफलतापूर्वक लाभ उठाकर यह 2040 तक वैश्विक वृद्धि में एक तिहाई योगदान दे सकता है। आईएमएफ की एशिया एवं प्रशांत विभाग की उप निदेशक एनी मेरी गुलडे वोल्फ ने कहा कि हम दक्षिण एशिया को वैश्विक वृद्धि केंद्र के रूप में आगे बढ़ता हुए देख रहे हैं।

<https://www.livehindustan.com/business/story-bharat-vaishvik-arthyavastha-ki-aguavi-karega-2830806.html>

निफ्ट पर जनवरी से नहीं लगेगा कोई चार्ज

नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) सुविधा के जरिए ऑनलाइन लेनदेन करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। इस सुविधा के लिए अब एक जनवरी 2020 से कोई शुल्क लागू नहीं होगा। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इसके लिए बैंकों को निर्देश दिये हैं। केंद्रीय बैंक ने निर्देश जारी किया है कि बचत खातों से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते समय एनईएफटी चार्ज नहीं लिये जाएंगे। नए साल से यह नियम लागू हो जाएगा। आरबीआई ने डिजिटल ट्रांजेक्शन को प्रमोट करने के लिए बैंकों को यह निर्देश दिया है। आपको बता दें कि इंटर-बैंक ट्रांसफर के आरटीजीएस और एनईएफटी दो सिस्टम हैं। ये दोनों सिस्टम आरबीआई की देखरेख में हैं। इन दोनों सिस्टम में इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग या फिर बैंक ब्रांच के माध्यम से ट्रांजेक्शन किया जा सकता है। एनईएफटी सुविधा का लाभ कोई भी व्यक्ति या कंपनी ले सकती है। इस सिस्टम के जरिए किसी अन्य शहर की बैंक शाखा में किसी भी कंपनी या व्यक्ति को पैसा भेजा जा सकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने एक स्टेटमेंट में कहा, 'रिजर्व बैंक का प्रयास अत्याधुनिक भुगतान प्रणालियों की स्थापना करना है, जो कुशल, सुविधाजनक, सुरक्षित और सस्ती हों। इस प्रयास के परिणामस्वरूप रिटेल डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स में तेजी से विकास देखने को मिलेगा।'

अक्टूबर 2018 से सितंबर 2019 की अवधि में कुल गैर-नकद रिटेल पेमेंट में डिजिटल पेमेंट्स का योगदान 96 फीसद रहा है। वही, इस अवधि में एनईएफटी और यूपीआई सिस्टम से क्रमशः 252 करोड़ और 874 करोड़ लेनदेन हुए।

इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने एनईएफटी की सुविधा को दिसंबर 2019 से 27/7 उपलब्ध कराने के लिए कहा था। गौरतलब है कि भारत के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने पहले तय किया है कि वह आरटीजीएस और एनईएफटी सुविधा से लेनदेन के लिए कोई चार्ज नहीं वसूलेगा। एनईएफटी सिस्टम से लेनदेन में इस समय 10,000 रुपये तक के लेनदेन पर दो रुपये व जीएसटी चार्ज लगता है।

<https://www.jagran.com/business/biz-good-news-for-those-dealing-with-neft-from-this-date-no-charge-19737708.html>

चावल निर्यातकों को झटका

चावल निर्यातकों को अब यूरोपीय यूनियन में शामिल देशों में चावल निर्यात करने से पहले किसी सरकारी एजेंसी से सर्टिफिकेट लेना होगा। दोनों प्रकार के लिए चावल बासमती और गैर बासमती के निर्यात के लिए यह नियम

लागू होगा। बुधवार को विदेश व्यापार महानिदेशालय की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना में कहा गया है कि किसी भी प्रकार के चावल निर्यात से पहले एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल या एजेंसी से सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा जो इस बात की गारंटी लेगा कि निर्यात होने वाले चावल में पेस्टिसाइड की मात्रा कम है और यह खतरनाक नहीं है। यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। दिल्ली, मुंबई, कोच्चि, कोलकाता और चेन्नई में सर्टिफिकेट एजेंसी के कार्यालय हैं।

यूरोप एक अमीर बाजार है और यहां अच्छी गुणवत्ता वाले प्रीमियम चावल लोग खाना पसंद करते हैं

यूरोप में चावल निर्यात करने वाले कारोबारियों ने बताया कि इस प्रकार की शर्तें निर्यात को और कम करेंगी। चावल निर्यातक पंकज गोयल ने बताया कि भारत के चावल में पेस्टिसाइड की मात्रा अधिक होती है जबकि पाकिस्तान के चावल में पेस्टिसाइड काफी कम होती है या नहीं होती है। उन्होंने बताया कि यही वजह है कि यूरोप से भारत को मिलने वाले आर्डर पाकिस्तान शिफ्ट हो रहे हैं। चावल निर्यातकों का कहना है कि यूरोप एक अमीर बाजार है जहां अच्छी कीमत मिलती है और अच्छी गुणवत्ता वाले प्रीमियम चावल लोग खाना पसंद करते हैं। डीजीएफटी के मुताबिक भारत से दो प्रकार के बासमती चावल पीबी1 और 1401 का निर्यात यूरोप में किया जाता है। भारत सालाना 3 लाख टन चावल का निर्यात यूरोप को करता है। गोयल कहते हैं पहले 4 लाख टन के आसपास यह निर्यात था जो कम हो रहा है।

<https://money.bhaskar.com/news/MON-ECN-FOR-rice-exporters-require-certification-of-inspection-to-export-to-european-union-126007742.html>

बीएसएनएल के 40,000 से अधिक कर्मचारियों ने लिया वीआरएस

सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के 40,000 से अधिक कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) का विकल्प ले चुके हैं। कंपनी द्वारा तीन दिन पहले इस योजना की घोषणा की गई है। कंपनी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक पी.के. पुरवार ने यह जानकारी दी है। बता दें कि सरकार ने पिछले महीने बीएसएनएल और महानगर दूरसंचार निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के पुनरोद्धार के लिए 69,000 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की थी। इसमें घाटे में चल रही दोनों कंपनियों का विलय करना, उनकी परिसंपत्तियों का मौद्रिकरण करना, कर्मचारियों को वीआरएस देना इत्यादि शामिल है। सरकार का इरादा है कि संयुक्त कंपनी को दो साल के भीतर लाभ में लाया जाए। बीएसएनएल ने पांच नवंबर को वीआरएस की घोषणा की। कंपनी के कुल डेढ़

लाख कर्मचारियों में से करीब एक लाख कर्मचारी वीआरएस के दायरे में हैं। मालूम हो कि वीआरएस आवेदन के लिए कर्मचारियों के पास तीन दिसंबर तक का समय है।

पुरवार ने कहा, 'वीआरएस योजना के लिए अब तक 40,000 से ज्यादा कर्मचारी रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इसमें से करीब 26,000 कर्मचारी समूह 'ग' के हैं। सभी श्रेणियों के कर्मचारियों से इस योजना को अच्छी प्रतिक्रिया मिली है।' बीएसएनएल का मानना है कि करीब 70 से 80 हजार कर्मचारी इस योजना को चुनेंगे। कंपनी का मनाना है कि इससे उसके वेतन भुगतान के खाते में करीब 7,000 करोड़ रुपये बचत हो सकती है। बीएसएनएल की वीआरएस योजना में कंपनी के 50 वर्ष या इससे अधिक आयु के सभी नियमित और स्थायी कर्मचारी इसके योग्य हैं। इसमें उन कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है जो प्रतिनियुक्ति पर बीएसएनएल से बाहर किसी अन्य संगठन या विभाग में नियुक्त हैं।

<https://www.jagran.com/business/biz-bsnl-40000-employees-availed-vrs-scheme-in-last-3-days-19739920.html>

अटल पेंशन योजना के सदस्यों की संख्या बढ़कर हुई 1.9 करोड़

अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के सदस्यों की संख्या 1.9 करोड़ से अधिक हो गई है। यह जानकारी पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए (ने दी। असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने यह योजना शुरू की है। नियामक ने बयान में कहा कि नामांकन बढ़ने का मुख्य कारण नए अटल पेंशन खाते खोलने के लिए बैंकों को दिए गए लक्ष्यों का पूरा होना है। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में अटल पेंशन योजना के नामांकन को अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। 31 अक्टूबर 2019 तक अटल पेंशन योजना के 36 लाख से ज्यादा खाते खोले गए हैं। यह 33 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। एक साल पहले की इसी अवधि में वृद्धि 26 प्रतिशत थी।

36 लाख एपीवाई खातों में 27.5 लाख खाते सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों 5.5 लाख खाते क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और करीब तीन लाख खाते निजी बैंक और भुगतान बैंक द्वारा खोले गए हैं। सार्वजनिक बैंक में भारतीय स्टेट बैंक का योगदान सबसे अधिक रहा। उसने 11.5 लाख अटल पेंशन खाते जोड़े। इसके बाद कैनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया का नंबर है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक ने सबसे ज्यादा अटल पेंशन खाते खोले हैं। भुगतान बैंक श्रेणी में एयरटेल पेमेंट बैंक ने चालू वित्त वर्ष में अब तक करीब 1.8 लाख पेंशन खाते खोले हैं। बयान में कहा गया

है कि पीएफआरडीए ने मार्च 2020 तक 2.25 करोड़ लोगों को इस पेंशन योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा है।

<https://www.livehindustan.com/business/story-atal-pension-yojana-member-increased-2831171.html>

ट्रंप पर कोर्ट ने लगाया 20 लाख डॉलर का जुर्माना

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर न्यूयॉर्क की एक अदालत ने करीब 15 करोड़ रुपये का भारी भरकम जुर्माना लगाया है। ट्रंप को उनके चौरिटेबल फाउंडेशन के गलत इस्तेमाल के लिए 20 लाख डॉलर (करीब 15 करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट में ट्रंप पर यह आरोप सही साबित हुए हैं कि उन्होंने अपने चौरिटेबल फाउंडेशन का इस्तेमाल अपने राजनीतिक और बिजनेस से जुड़े हितों को साधने के लिए किया था। रिपोर्ट के मुताबिक, न्यायाधीश सैलियन स्क्रापुला ने गुरुवार को इस मामले पर अपना निर्णय सुनाते हुए यह भी आदेश दिया कि ट्रंप फाउंडेशन को बंद कर दिया जाए और इस फाउंडेशन के बाकी बचे हुए फंड (करीब 17 लाख डॉलर) को अन्य गैर लाभकारी संगठनों में बांट दिया जाए। मामले की सुनवाई के दौरान ट्रंप ने आरोप स्वीकार कर लिया था।

गौरतलब है कि ट्रंप पर यह मुकदमा पिछले साल दायर हुआ था। ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने अपने चौरिटी फाउंडेशन का पैसा 2016 संसदीय चुनाव प्रचार में खर्च किया था। अटॉर्नी जनरल जेम्स ने यह मुकदमा दायर करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप पर 2.8 मिलियन (28 लाख) डॉलर क्षतिपूर्ति लगाने की मांग की थी। न्यायाधीश स्क्रापुला ने इस राशि को कम करते हुए 20 लाख डॉलर कर दिया। फाउंडेशन के वकील ने पहले कहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप पर यह मुकदमा राजनीति से प्रेरित है।

<https://money.bhaskar.com/news/MON-ECN-POLI-judge-says-trump-must-pay-2-million-dollar-over-misuse-of-foundation-funds-126019410.html>

किसानों की आय बढ़ाएंगे नैनो तकनीक वाले खाद

किसानों का आय दोगुना करने के मद्देनजर सरकार कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसी कड़ी में देसी कंपनी ने नैनो प्रौद्योगिकी पर आधारित ऐसे उर्वरक पेश किए हैं जिनसे पैदावार 30 फीसदी तक अधिक होगी।

इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजेशन कांफ़ेरेटिव (इफको) ने फसलों की पैदावार में 15 से 30 प्रतिशत तक वृद्धि करने वाले नैनो नाइट्रोजन, नैनो जिंक और नैनो कॉपर उत्पाद को क्षेत्र परीक्षण के लिए रविवार को जारी कर दिया। उर्वरक एवं रसायन मंत्री डी. बी. सदानंद गौड़ा ने उर्वरक क्षेत्र की दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी संस्था इफको की मातृ इकाई गुजरात के कलोल में एक समारोह में नैनो



प्रौद्योगिकी आधारित नैनो नाइट्रोजन, नैनो जिंक और नैनो कॉपर का लोकार्पण किया।

उन्होंने इन उत्पादों के क्षेत्र परीक्षण करने की भी घोषणा की। गौड़ा ने कहा कि नैनो उत्पाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ग्रीन परियोजना का हिस्सा है। इसकी मदद से न केवल किसानों की आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी बल्कि इससे मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होगा।

<https://www.livehindustan.com/business/story-nano-technique-wali-khad-se-badegi-kisano-ki-paidawar-jaane-khasiyat-2830835.html>

राम मंदिर से बदलेगी अयोध्या की अर्थव्यवस्था, रोजगार की भी संभावना

राम जन्मभूमि परिसर को लेकर सौ साल से अधिक पुराना विवाद सुलझने के बाद अयोध्या की अर्थव्यवस्था में जबरदस्त बदलाव आएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अयोध्या में वृष्णो देवी और तिरुपति की तर्ज पर एक नया और उससे भी बड़ा धार्मिक पर्यटन केंद्र का विकास होगा। वहां रोजाना एक लाख तक श्रद्धालु और पर्यटक पहुंच सकते हैं। इससे अयोध्या और इसके आसपास के एक बड़े हिस्से पर्यटन अर्थव्यवस्था का विकास होगा। इससे बड़े पैमाने पर रोजगार का भी सृजन होगा।

इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक मुंबई के एक शेरार कारोबारी विजय केडिया ने कहा कि अयोध्या में मंदिर और मस्जिद बनने और शांति स्थापित होने से वहां पर्यटकों और श्रद्धालुओं का तांता लग जाएगा। पर्यटकों की संख्या रोजाना एक लाख तक भी पहुंच सकती है। यह वैष्णो देवी और तिरुपति से भी बड़ा धार्मिक पर्यटन केंद्र बन सकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का बड़ा योगदान है। यदि भारत को पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है, तो उत्तर प्रदेश को कम से कम एक लाख करोड़ डॉलर का योगदान करना होगा।

जानकारों का मानना है कि अयोध्या का मसला सुलझने से पूरी दुनिया के निवेशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर भरोसा बढ़ेगा। केआर चोकसी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के एमडी देवेन चोकसी ने कहा कि बाजार पर इस फैसले का सकारात्मक असर पड़ेगा। विवाद को खत्म करने के

किसी भी फैसले से निवेशकों में बहुत अच्छा संकेत जाएगा।

आईआईएफएल सिक्युरिटीज के एक्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट फॉर मार्केट संजीव भसीन ने कहा कि ताजा फैसले से यह पता चलता है कि सरकार ऐसा काम कर रही है, जो पिछले 70 साल में नहीं हुआ। पहले कश्मीर में धारा 370 को अप्रभावी बनाया गया और अब अयोध्या का विवाद सुलझाया गया। उम्मीद है कि कई और सुधार होंगे। मूडीज द्वारा देश के आउटलुक को नकारात्मक किए जाने के बाद संभव है कि सरकार लांग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और व्यक्तिगत आयकर में कुछ कटौती करे। इन सब बातों का शेयर बाजार पर अनुकूल असर दिखेगा और यह जल्द ही नई ऊंचाई छूएगा।

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने शनिवार को अयोध्या विवाद पर फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा कि 2.77 एकड़ की संपूर्ण विवादित भूमि हिंदू पक्ष को मिल जाएगी। इसके आसपास सरकार ने जो 67 एकड़ भूमि अधिगृहीत की है, मुस्लिम पक्ष चाहें तो मस्जिद बनाने के लिए उसमें से या किसी अन्य जगह पर भूमि ले सकते हैं। मंदिर के निर्माण के लिए तीन महीने के अंदर एक ट्रस्ट बनाया जाएगा, जिसे विवादित जमीन सौंप दी जाएगी।

<https://money.bhaskar.com/news/MON-ECN-POLI-resolution-of-ram-janmabhoomi-dispute-will-change-the-economy-of-ayodhya-126026134.html>

ईरान को मिला विशाल पेट्रोलियम भंडार



ईरान ने एक बड़ा तेल क्षेत्र खोज निकालने का दावा किया है। ईरान के दक्षिणी प्रांत में पाए गए इस तेल क्षेत्र में करीब 5,300 करोड़ बैरल कच्चा तेल होने का अनुमान लगाया गया है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रुहानी ने कहा कि इस खोज के बाद उनके तेल भंडार में एक-तिहाई का इजाफा हो जाएगा। रुहानी ने सरकारी टीवी के जरिये इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि अमेरिकी प्रतिबंध के बावजूद ईरान की इकोनॉमी सुचारु रूप से चल रही है।

जानकारी के मुताबिक 80 मीटर गहरा यह तेल भंडार ईरान की इराक से लगी खुजिस्तान सीमा से लेकर ओमीदिया शहर तक 200 किलोमीटर दायरे में फैला हुआ है। रुहानी ने

अपने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि यह सरकार द्वारा लोगों को दिया गया एक छोटा सा उपहार है। अमेरिका द्वारा लगातार कष्टकारी प्रतिबंध लगाने के बावजूद हम आज एक अमीर देश बन गए हैं। ईरान की ऑयल इंडस्ट्री के कर्मचारियों ने एक बड़ा तेल क्षेत्र खोज निकाला है।

इस खोज के बाद ओपेक देशों के कुल तेल भंडार में 34 परसेंट का इजाफा हो जाएगा। गौरतलब है कि ईरान तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के संस्थापक देशों में शामिल है। तेल भंडार के मामले में वह पहले से ही दुनिया का पांचवा बड़ा देश है। अगर इस तेल खोज का दावा साबित हो जाता है, तो ईरान तेल भंडार के मामले में तीसरे स्थान पर आ जाएगा। तेल के खजाने पर बैठा ईरान प्रतिबंधों के चलते अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहा है। अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों ने उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं।

पिछले वर्ष अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2015 में ईरान के साथ हुई परमाणु संधि से हाथ खींच लिए थे और उसपर फिर से प्रतिबंध लगा दिए थे। ईरान की इकोनॉमी पर इन प्रतिबंधों का बहुत बुरा असर हुआ है। इसके साथ ही भारत भी ईरान पर प्रतिबंधों से प्रभावित हुआ है। गौरतलब है कि भारत बड़े पैमाने पर ईरान से कच्चा तेल आयात करता रहा है।

<https://www.jagran.com/business/biz-iran-discovers-new-oil-field-with-50-billion-barrels-of-crude-says-iranian-president-hassan-rouhani-19745182.html>

देश सेवा के लिए समर्पित रहा दत्तोपंत ठेंगड़ी का जीवन

स्वदेशी जागरण मंच के संस्थापक दत्तोपंत ठेंगड़ी के जन्म शताब्दी वर्ष के प्रारंभ पर गीतांजलि विहार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान दत्तोपंत ठेंगड़ी की ओर से देश एवं समाज सेवा के लिए किए गए कार्यों को याद किया गया।

स्वदेशी जागरण मंच की जिला महिला प्रमुख नीरज सिंह ने बताया कि दत्तोपंत ठेंगड़ी भारतीय मजदूर संघ एवं भारतीय किसान संघ के भी संस्थापक थे। डंकल प्रस्ताव के विरोध में व्यापक जन आंदोलन खड़ा कर उन्होंने आपत्ति दर्ज की थी। इस मौके पर महानगर महिला प्रमुख भारती सिंह ने कहा कि दत्तोपंत ठेंगड़ी अपने मन, कर्म और वचन से समाज को दिशा देना वाले और व्यवहार से राष्ट्र का उत्थान करने का ध्येय रखते थे। वह समाज के हर वर्ग को लेकर चिंतित रहते थे। इस दौरान संगठन की महिला इकाई की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया बबीता चौहान को महिला इकाई महानगर विचार विभाग प्रमुख, अंजली चौधरी को महिला इकाई महानगर कोष प्रमुख, ज्योति गोयल को महिला इकाई महानगर सह-संपर्क प्रमुख एवं निधि गोयल को महिला इकाई महानगर सह-प्रचार प्रमुख की जिम्मेदारी दी गई। □□

<https://www.jagran.com/uttarakhand/haridwar-dattopanth-thengadi-birthday-19742755.html>

स्वदेशी गतिविधियाँ
स्वदेशी मेला
 15-21 अक्टूबर 2019 (झारका, नई दिल्ली)

सचित्र झलकियाँ



प्रांत सम्मेलन, हिमाचल प्रदेश

सचित्र झलकियाँ



प्रांत सम्मेलन, जोधपुर

सचित्र झलकियाँ



स्वदेशी गतिविधियां

चीन के सामान व सेवाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन

सचित्र शलकियां



उदयपुर, राजस्थान



उड़ीसा



मुसदाबाद, उत्तर प्रदेश



जोधपुर, राजस्थान



जमशेदपुर, झारखंड



हापड़, उत्तर प्रदेश



गवालिपूर, मध्य प्रदेश



बीकानेर, राजस्थान



भीलवाड़ा, राजस्थान



भरतपुर, राजस्थान



बाड़मेर, राजस्थान



अजमेर, राजस्थान

दत्तोपंत ठेंगड़ी जन्मशताब्दी वर्ष

2019 - 2020



प्रयागराज, उत्तर प्रदेश



झारखंड



वैद्यनाथ, कर्नाटक

प्रकाशक व मुद्रक ईश्वरदास महाजन द्वारा स्वदेशी जागरण समिति के लिए काम्पीटेंट बाईन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली से मुद्रित और धर्मक्षेत्र, सेक्टर-8, रामाकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली-110022 से प्रकाशित, संपादक: अजेय भारती